

जन जन की बात जन जन तक

साप्ताहिक

जन जन विचार



বাইজৰ কথা বাইজৰ মাজলৈ সাপ্তাহিক

জন জন বিচাৰ

WEEKLY TRILINGUAL NEWSPAPER

Language : Hindi, Assamese & English

WEBSITE : www.janjanvichar.in

VOICE OF ALL, FOR ALL WEEKLY

JAN JAN VICHAR

RNI Regd No. ASMUL/25/A2367::Guwahati, Friday, 9 October 2026 :: Year-1 Vol-39 Issue-18 :: शुक्रवार। 9 अक्टूबर 2026। शक संवत 1948। आश्विन। कृष्ण। चतुर्दशी। ::

जन चिंतन

धनेश्वर चौधरी

ज्ञानेश कुमार के बहाने बढ़ता राजनीतिक शोर

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। सड़कों पर प्रदर्शन, धरना, हिरासत और प्राथमिकी तक मामला पहुंच चुका है। सवाल यह नहीं कि विपक्ष को विरोध का अधिकार है या नहीं- वह अधिकार लोकतंत्र का मूल हिस्सा है। असली सवाल यह है कि क्या इस आंदोलन के पीछे उठाए गए आरोप उतने ही ठोस हैं, जितना उनका राजनीतिक शोर ?

विपक्ष से पहला सवाल-यदि मतदाता सूची में गंभीर गड़बड़ी हुई है, तो वह पूरे आंकड़े, प्रभावित मतदाताओं की सूची और प्रमाण सार्वजनिक क्यों नहीं करता ? केवल यह कहना कि चुनावी व्यवस्था प्रभावित हो रही शेष पृष्ठ 2 पर

राहुल की 'धप्पा' राजनीति

जन जन विचार

...✍ नई दिल्ली

राजनीति में कई बार संदेश भाषण से नहीं, बल्कि अचानक उठाए गए एक कदम से जाता है। राहुल गांधी की हाल की राजनीति में ऐसा ही एक पैटर्न उभरता दिखाई दे रहा है। पिछले करीब दो महीनों में तीन मौकों पर उन्होंने विरोध-प्रदर्शन की तय पटकथा को अचानक बदल दिया। पुलिस ने एक जगह घेरा बनाया, राहुल दूसरी जगह पहुंच गए। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर आंदोलन खत्म करने की तैयारी की, तो उन्होंने नया मोर्चा खोल दिया।

कांग्रेस ने इसे मजाकिया अंदाज में 'धप्पा' कहा है। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह सिर्फ एक नारा या सोशल मीडिया का जुमला नहीं, बल्कि विरोध की एक नई शैली का संकेत है-अचानक पहुंचो, व्यवस्था को प्रतिक्रिया के लिए मजबूर करो और कैमरों का फोकस अपने पक्ष में मोड़ दो।

सबसे ताजा उदाहरण आकाशवाणी भवन का है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस के शेष पृष्ठ 3 पर



राहुल-प्रियंका पर एफआईआर

नई दिल्ली। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में विपक्ष के लगातार प्रदर्शन के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एक और प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस के अनुसार, बुधवार को हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ कथित मारपीट और उनके सरकारी कर्तव्य में बाधा डालने के आरोप में यह कार्रवाई की गई है। मामले में कांग्रेस के कई अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं के नाम भी शामिल किए गए हैं।

चुनाव आयोग की अग्निपरीक्षा

जन जन विचार

...✍ नई दिल्ली

भारतीय राजनीति में इन दिनों सबसे तीखा संघर्ष किसी चुनावी मैदान में नहीं, बल्कि उस संस्था की विश्वसनीयता को लेकर दिखाई दे रहा है जो देश में चुनाव कराती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर राहुल गांधी और विपक्ष का लगातार सड़क पर उतरना इसी बड़े संघर्ष का हिस्सा है।

लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि ज्ञानेश कुमार इस्तीफा देंगे या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या निर्वाचन आयोग पर राजनीतिक अविश्वास इतना गहरा हो गया है कि विपक्ष अब उसके प्रमुख के इस्तीफे को लोकतांत्रिक संघर्ष का केंद्रीय मुद्दा बना रहा है ?

राहुल गांधी और कांग्रेस का आरोप है कि मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितताएं हुई हैं और इससे मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। निर्वाचन आयोग इन आरोपों को खारिज करता रहा है और उसका कहना है कि मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार चलती है।

यहीं से यह विवाद केवल राहुल गांधी बनाम ज्ञानेश कुमार नहीं रह जाता। यह सवाल बन जाता है- निर्वाचन व्यवस्था पर भरोसा कौन कायम शेष पृष्ठ 3 पर



विपक्ष का देशव्यापी हल्लाबोल, जनता परेशान

नई दिल्ली/पटना/बेंगलुरु

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन गुरुवार को देश के कई हिस्सों में फैल गया। लगातार तीसरे दिन दिल्ली में कांग्रेस और विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसद और नेता कनॉट प्लेस से राजघाट पहुंचे और वहां शांतिपूर्ण धरना दिया। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ विपक्षी नेताओं की बैठक हुई।

विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हैं और चुनाव आयोग को इन पर जवाब देना चाहिए। विपक्षी दल इसी मुद्दे को लेकर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। चुनावी प्रक्रिया और एसआईआर को लेकर सरकार तथा विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव लगातार बढ़ रहा है।

पहले दो दिनों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव तथा हिरासत की घटनाओं के बाद गुरुवार को विपक्ष ने राजघाट का रुख किया। दिल्ली पुलिस की



मौजूदगी में बसों से नेता राजघाट पहुंचे। वहां राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और मौन प्रदर्शन किया।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि विपक्ष को पहले चुनाव आयोग और फिर जंतर-मंतर तक जाने से रोका गया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीईसी ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। ये आरोप विपक्ष की राजनीतिक दलील का हिस्सा हैं, जिनका सरकार और भाजपा विरोध करती रही है।

पटना में तेजस्वी के नेतृत्व में मार्च

बिहार की राजधानी पटना में राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी शहीद स्मारक से राजभवन की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के पास मार्च रोक दिया। तेजस्वी यादव ने एसआईआर और चुनावी प्रक्रिया को लेकर सरकार तथा चुनाव आयोग पर सवाल उठाए और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग दोहराई।

बेंगलुरु में भी सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी

बेंगलुरु में भी सीईसी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। नागरिक समूहों और 'कॉकरोच जनता पार्टी' से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे वापस लेने और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। इस तरह दिल्ली से पटना और बेंगलुरु तक विरोध का मुद्दा एक ही रहा—मतदाता सूची, चुनावी प्रक्रिया और चुनाव आयोग की भूमिका पर विपक्ष के सवाल।

सवाल अब केवल विरोध का नहीं, जवाबदेही का भी

विपक्ष का आंदोलन लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार और चुनावी पारदर्शिता का प्रश्न उठा रहा है। दूसरी ओर, कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। ऐसे में असली कसौटी यह होगी कि राजनीतिक आरोपों से आगे बढ़कर एसआईआर और मतदाता सूची से जुड़े सवालों का तथ्यात्मक जवाब कितना स्पष्ट मिलता है।

चुनाव लोकतंत्र की सबसे बुनियादी संस्था है। इसलिए चुनाव आयोग पर उठने वाले सवालों को केवल राजनीतिक आरोप कहकर खारिज करना पर्याप्त नहीं होगा और विपक्ष के आरोपों को बिना प्रमाण अंतिम सत्य मान लेना भी उचित नहीं। जरूरत है कि मतदाता सूची और एसआईआर से जुड़े प्रत्येक गंभीर सवाल का आंकड़ों और दस्तावेजों के साथ पारदर्शी जवाब सामने आए। लोकतंत्र में सड़क का संघर्ष अंततः संस्थागत जवाबदेही में ही बदलना चाहिए।

असम में कांग्रेस का प्रदर्शन, बोरा चोटिल

जन जन विचार
...✍गुवाहाटी

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर नई दिल्ली में विपक्षी सांसदों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 8 अक्टूबर को राज्यभर में प्रदर्शन किया। गुवाहाटी के राजीव भवन में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेड तोड़कर मार्च निकालने की कोशिश की, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पूर्व असम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व राज्यसभा सांसद रिपुन बोरा और प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष मीरा बरठाकुर गोस्वामी समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। कांग्रेस ने दावा किया कि पुलिस के साथ धक्का-मुक्की में बोरा के पैर में चोट लगी और उन्हें टांके लगवाने पड़े। बोरा ने कहा कि मतदाता सूची से कथित तौर पर नाम हटाए जाने के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा और विरोध करना उसका लोकतांत्रिक अधिकार है।

गुवाहाटी के अलावा डिब्रूगढ़, डिफू, नगांव, नलबाड़ी और चराइदेव में भी प्रदर्शन हुए। कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों ने ज्ञानेश कुमार और केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए तथा पुतले फूंके।

पृष्ठ 1 का शेषांश...

ज्ञानेश कुमार के बहाने...

है, जनता के विश्वास को मजबूत नहीं करता। प्रमाण चाहिए, तथ्य चाहिए और संसद तथा न्यायपालिका के सामने ठोस आधार चाहिए।

लेकिन सवाल ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयोग से भी कम नहीं हैं। यदि मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर इतने गंभीर संदेह पैदा हुए हैं, तो आयोग हर आपत्ति का बिंदुवार और सार्वजनिक उत्तर देने में संकोच क्यों करे? निर्वाचन आयोग केवल चुनाव कराने वाली संस्था नहीं, बल्कि मतदाता के विश्वास की संवैधानिक धुरी है। उस पर उठे सवालों का उत्तर राजनीतिक तकरार से नहीं, आंकड़ों और पारदर्शिता से मिलना चाहिए।

और तीसरा सवाल कांग्रेस तथा उसके सहयोगियों से-क्या सड़क पर लगातार टकराव ही आंदोलन की अंतिम रणनीति है? यदि संवैधानिक पदाधिकारी को हटाने की मांग है, तो उसके लिए संवैधानिक रास्ते भी मौजूद हैं। संसद में प्रस्ताव और न्यायिक प्रक्रिया का रास्ता छोड़कर हर बार सड़क पर शक्ति प्रदर्शन करने से क्या मूल मुद्दा मजबूत होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया भी साधारण राजनीतिक मांग से अलग संवैधानिक प्रक्रिया है।

सवाल सीधा है-ज्ञानेश कुमार को अपनी निष्पक्षता साबित करने के लिए कितना और क्या सार्वजनिक करना होगा, और कांग्रेस को अपने आरोप साबित करने के लिए कितने ठोस प्रमाण देने होंगे?

लोकतंत्र में न निर्वाचन आयोग सवालों से ऊपर है, न विपक्ष आरोपों से। जनता दोनों से जवाब चाहती है-साफ, प्रमाणित और संविधान की कसौटी पर।

राशिफल

9 से 15 अक्टूबर, 2026 ॥ विक्रम संवत 2083-**मास** : आश्विन, **पक्ष** : कृष्ण, **तिथि** :चतुर्दशी

मेष : सप्ताह की शुरुआत उत्साह से होगी। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें। परिवार में किसी सदस्य से मतभेद हो सकते हैं।

वृषभ : के हुए काम पूरे होने के योग हैं। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और व्यापार में लाभ के अवसर बनेंगे। निवेश करते समय जल्दबाजी न करें। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। यात्रा लाभदायक हो सकती है।

मिथुन : कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा की सराहना होगी। नए संपर्क भविष्य में लाभ दे सकते हैं। आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है। पुराने मित्र से मुलाकात मन प्रसन्न करेगी। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न बरतें।

कर्क : इस सप्ताह मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। नौकरी में पद और प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। व्यापार में नई योजना पर काम शुरू होगा। परिवार में सुख-शांति रहेगी। भावनात्मक निर्णय लेने से बचें।

सिंह : नेतृत्व क्षमता के बल पर महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे। करियर में आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। धन की स्थिति अच्छी रहेगी, हालांकि खर्च भी बढ़ सकते हैं। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

कन्या : योजनाओं को पूरा करने के लिए धैर्य रखना होगा। कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक लाभ के योग हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। स्वास्थ्य में सुधार महसूस होगा।

तुला : नए अवसर सामने आएंगे। नौकरी बदलने या नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो समय अनुकूल हो सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर।

वृश्चिक : सप्ताह मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन मेहनत का फल भी मिलेगा। धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें। किसी पुराने विवाद को बातचीत से सुलझाने का प्रयास करें।

धनु : भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी और व्यापार में प्रगति के संकेत हैं। रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। यात्रा के योग बन रहे हैं। विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा।

मकर : करियर के लिहाज से सप्ताह महत्वपूर्ण है। नई जिम्मेदारियां भविष्य में लाभ देंगी। व्यापारियों को नए सौदे मिल सकते हैं। खर्च पर नियंत्रण रखें। घर-परिवार में किसी बुजुर्ग की सलाह उपयोगी साबित होगी।

कुंभ : लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में सहयोगियों का साथ मिलेगा। आर्थिक लाभ के अवसर आएंगे, लेकिन जोखिम भरे निवेश से बचें। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। स्वास्थ्य को लेकर दिनचर्या व्यवस्थित रखें।

मीन : रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। नौकरी में सकारात्मक बदलाव के संकेत हैं। व्यापार में लाभ हो सकता है। परिवार में किसी शुभ समाचार से खुशी मिलेगी। प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा। मानसिक शांति के लिए स्वयं को पर्याप्त समय दें।

सप्ताह के पर्व/त्योहार

9 अक्टूबर (शुक्रवार) : चतुर्दशी श्राद्ध
10 अक्टूबर (शनिवार) : श्राद्ध अमावस्या
11 अक्टूबर (रविवार) : शारदीय नवरात्र आरंभ, कलश स्थापन
14 अक्टूबर (बुधवार): वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत

●ज्योतिर्विद् आचार्य अखिलेश्वर शुक्ल
भाग्योदय : पहला तल्ला, सेंट्रल प्लाजा, एमएस रोड
फैंसी बाजार, गुवाहाटी-781001 मो.-94350 40387

धन दिशा



ताकि बीमा का क्लेम न हो रद्द

हमने पिछले अंक में स्वास्थ्य बीमा लेने की बात की थी। मान लेते हैं आपने ले लिया। लेकिन एक कड़वी सच्चाई यह है - बीमा खरीदना काफी नहीं। पिछले वित्त वर्ष में भारत में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के स्वास्थ्य बीमा क्लेम रद्द हुए। यानी लाखों परिवारों ने साल भर प्रीमियम भरा और अस्पताल में जरूरत पड़ने पर खाली हाथ रहे।

यह धोखा नहीं है-यह जानकारी का अभाव है। और इस अभाव को आज दूर करते हैं।

पहला कारण: पहले से बीमारी छुपाना-पॉलिसी लेते वक्त अगर शुगर, बीपी, थायराइड या कोई पुरानी बीमारी थी और आपने फॉर्म में 'नहीं' लिखा- तो उससे जुड़ा क्लेम कभी नहीं मिलेगा। आईआरडीएआई के आंकड़ों के अनुसार 30-40 प्रतिशत बड़े क्लेम इसी वजह से रद्द होते हैं। पुरानी बीमारी छुपाएं नहीं, घोषित करें। कुछ बीमारियों पर 2-4 साल का 'वेटिंग पीरियड' होता है-इसके बाद क्लेम मिलता है।

दूसरा कारण : रूम रेंट की सीमा - सस्ती पॉलिसियों में कमरे के किराए की सीमा होती है, जैसे 2,000 रुपए प्रतिदिन। अगर आपने 4,000 रुपए वाला कमरा लिया तो बीमा कंपनी पूरे बिल का सिर्फ आधा देती है - कमरा ही नहीं, डॉक्टर फीस, दवाइयां-सब पर अनुपातिक कटौती होती है। पॉलिसी लेते वक्त यह सीमा जरूर देखें।

तीसरा कारण : नेटवर्क अस्पताल से बाहर- कैशलेस क्लेम सिर्फ बीमा कंपनी के नेटवर्क अस्पताल में मिलता है। इमरजेंसी में दूसरे अस्पताल गए तो पहले खुद पैसे देने होंगे, फिर रिम्बर्समेंट क्लेम करना होगा-जिसमें सभी दस्तावेज चाहिए।

चौथा कारण : वेटिंग पीरियड के दौरान भर्ती - नई पॉलिसी लेने के 30 दिन के भीतर (दुर्घटना छोड़कर) कोई क्लेम नहीं मिलता। पहले से बीमारियों पर 2-4 साल की प्रतीक्षा। यह नियम पढ़ें और याद रखें।

क्लेम रद्द हो जाए तो क्या करें? घबराएं नहीं। पहले बीमा कंपनी के शिकायत प्रकोष्ठ में लिखित शिकायत करें। संतुष्ट न हों तो बीमा लोकपाल के पास जाएं-यह बिल्कुल मुफ्त है और 30 दिन में फैसला होता है।

बीमा लेना पहला कदम है, उसे समझना दूसरा। यह दूसरा कदम उठाने में आज देर न करें।

अगले हफ्ते : बच्चों की पढ़ाई का खर्च - अभी से सोचें, तो बाद में कर्ज नहीं लेना पड़ेगा।

इस कॉलम के लिए आपका कोई सवाल है? हमें भेजिए

-कोमल जैन
पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट, संस्थापक, वेल्थप्लायर्स- मो. 9004510577

नशामुक्ति दिवस पर अणुव्रत समिति का नुक्कड़ नाटक

जन जन विचार
...✍ गुवाहाटी



अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह के अंतर्गत अणुव्रत विश्व भारती सोसायटी के तत्वावधान में पंचम दिवस : नशामुक्ति दिवस के अवसर पर अणुव्रत समिति, गुवाहाटी द्वारा को अच्युत स्क्वायर, रेलवे गेट नंबर 2 के पास, राम मंदिर लेन में एक प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक का आयोजन प्रात: 10 बजे किया गया। इस नुक्कड़ नाटक ने उपस्थित लोगों के बीच नशे के दुष्परिणामों को लेकर गहरी जागरूकता पैदा की। नाटक का निर्देशन व मुख्य अभिनय अवकाश कुमार जम्मड़ ने किया। नाटक में अब्दुल कय्यूम ने भी अभिनय किया। अभिनय के दौरान कलाकारों के चेहरे के भाव, संवादों की गंभीरता और परिस्थितियों के अनुरूप उनकी भावनात्मक प्रस्तुति ने दर्शकों को भीतर तक झकझोर दिया। दोनों कलाकारों ने अपने सशक्त अभिनय, भावपूर्ण संवाद अदायगी और प्रभावशाली हाव-भाव के माध्यम से नशे की गिरफ्त में फंसते व्यक्ति, उसके परिवार तथा समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया।

समिति की मंत्री श्रीमती रंजना बरडिया ने बताया कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया कि नशा केवल एक व्यक्ति के जीवन को ही नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार और समाज के भविष्य को प्रभावित करता है। नुक्कड़ नाटक का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं, बल्कि आमजन को यह समझाना था कि नशामुक्त समाज का निर्माण प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। इसके के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने, परिवारों को अपने बच्चों के प्रति जागरूक रहने तथा समाज के प्रत्येक वर्ग को नशे के खिलाफ सामूहिक रूप से आवाज उठाने का संदेश दिया।

इस अवसर पर अणुव्रत समिति के अध्यक्ष संजय चौरड़िया, अणुविभा के कार्यकारिणी सदस्य एवं समिति के निवर्तमान अध्यक्ष बजरंग बैद, उपाध्यक्ष श्रीमती सरोज बरडिया, अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह के मुख्य संयोजक सहमंत्री राजकुमार भटेरा ने अपने भावों को प्रस्तुत करते हुए कहा कि अणुव्रत का उद्देश्य व्यक्ति के भीतर संयम, नैतिकता और अच्छे संस्कारों को जागृत करना है। नशामुक्ति इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि नुक्कड़ नाटक जैसे सशक्त माध्यमों के जरिए समाज के हर वर्ग तक संदेश सरल और प्रभावी तरीके से पहुंचाया जा सकता है।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने कलाकारों की प्रस्तुति को सराहा और नशामुक्त समाज के निर्माण के संकल्प के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। नुक्कड़ नाटक ने यह संदेश स्पष्ट रूप से दिया कि नशा जीवन को नहीं, जीवन नशे को हराए और स्वस्थ, संस्कारित एवं जागरूक समाज के निर्माण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भूमिका निभानी होगी।

इस अवसर पर संगठन मंत्री श्रीमती राखी बैंगानी के साथ श्रीमती गुलाब दुगड़, श्रीमती नीलम चंडालियां, निर्मल बैद, संदीप बैद एवं राकेश श्यामसुखा उपस्थित थे। कार्यक्रम के सफल आयोजन में अणुव्रत समिति, गुवाहाटी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। समिति ने सभी समाजबंधुओं से ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया।

पृष्ठ 1 का शेषांश...

चुनाव आयोग की अग्निपरीक्षा

करेगा और उस भरोसे की कसौटी क्या होगी?

'मत चोरी' से शुरू हुई राजनीतिक लड़ाई : राहुल गांधी ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को अपने राजनीतिक अभियान का प्रमुख मुद्दा बना दिया है। उनका आरोप है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन की प्रक्रिया में ऐसी अनियमितताएं हुई हैं जिनका असर चुनाव की निष्पक्षता पर पड़ सकता है।

विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि निर्वाचन आयोग अपनी प्रक्रिया और आंकड़ों को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करे।

दूसरी ओर निर्वाचन आयोग का पक्ष है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण कानून और निर्धारित प्रक्रिया के तहत होता है। आयोग यह भी कह चुका है कि उसके निर्णय सामूहिक विचार-विमर्श के बाद लिए जाते हैं। यानी एक तरफ आरोप है, दूसरी तरफ खंडन। लेकिन लोकतंत्र में केवल आरोप और खंडन से बात पूरी नहीं होती। जहां संदेह पैदा हो, वहां दस्तावेज, आंकड़े और पारदर्शी जवाब ही विश्वास बहाल कर सकते हैं।

सबसे महत्वपूर्ण सवाल - ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति में राहुल भी थे : इस पूरे विवाद का एक ऐसा पहलू है जिस पर राजनीतिक बहस में अपेक्षाकृत कम चर्चा होती है।

ज्ञानेश कुमार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करने वाली चयन समिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल थे। यानी जिस नियुक्ति पर आज विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं, उस समय वे स्वयं उस चयन प्रक्रिया का हिस्सा थे। यह तथ्य अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। क्या समस्या ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति से है? या उनके पद संभालने के बाद निर्वाचन आयोग के निर्णयों और कार्यप्रणाली से? यदि शिकायत वर्तमान निर्णयों से है तो उन निर्णयों पर ठोस सवाल और प्रमाण सामने आने चाहिए। और यदि समस्या नियुक्ति की पूरी व्यवस्था से है तो फिर बहस केवल ज्ञानेश कुमार तक सीमित नहीं रह सकती। मामला व्यक्ति से आगे बढ़कर व्यवस्था का हो जाता है।

क्या सड़क का आंदोलन किसी संवैधानिक पद से इस्तीफा दिला सकता है? यहां राजनीति और संविधान के बीच अंतर समझना आवश्यक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल राजनीतिक प्रदर्शन या सड़क पर दबाव बनाकर पद से हटाया नहीं जा सकता। संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान कठोर रखी गई है। इसके लिए संसद में निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। इसका अर्थ साफ है—राजनीतिक आंदोलन दबाव बना सकता है, लेकिन पद से हटाने का अंतिम निर्णय संवैधानिक प्रक्रिया से ही होगा।

विपक्ष पहले भी ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर संसद में प्रस्ताव की दिशा में आगे बढ़ चुका है। लेकिन उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में संवैधानिक और संसदीय स्तर पर बाधाएं सामने आईं।

इससे साफ है कि यह लड़ाई केवल सड़कों पर नहीं लड़ी जा रही। इसका एक महत्वपूर्ण मैदान संसद भी है। निर्वाचन आयोग कोई सामान्य सरकारी कार्यालय नहीं है। सरकारें बदलती हैं, राजनीतिक दल सत्ता में आते-जाते हैं, लेकिन चुनाव कराने वाली संस्था की निष्पक्षता पर विश्वास बना रहना चाहिए। इसीलिए यदि विपक्ष मतदाता सूची पर सवाल उठाता है तो उसका जवाब तथ्यों के साथ दिया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ केवल राजनीतिक आरोप को प्रमाण मान लेना भी लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए उचित नहीं होगा।

संपादकीय

नाना पाटेकर : पर्दा गिरा आवाज रह गई

कुछ कलाकार पर्दे पर दिखाई देते हैं, कुछ स्मृतियों में। नाना पाटेकर उन विरले कलाकारों में थे, जो अभिनय समाप्त होने के बाद भी दर्शकों के भीतर बने रहते थे। उनके निधन से भारतीय सिनेमा ने एक अभिनेता ही नहीं, एक ऐसी संवेदनशील आवाज खो दी है, जिसमें जीवन की खुरदरी सच्चाइयां सुनाई देती थीं।

रंगमंच से निकले नाना ने सिनेमा को चमक का माध्यम भर नहीं माना। 'परिंदा', 'प्रहार', 'क्रांतिवीर', 'खामोशी', 'सलाम बॉम्बे' से लेकर 'वेलकम' तक उनके किरदार बदलते रहे, लेकिन उनमें मनुष्य की धड़कन हमेशा मौजूद रही। वे पात्र को निभाते नहीं थे, उसके भीतर उतर जाते थे। उनकी आवाज में एक अलग ही ताप था–कठोरता के भीतर करुणा और आक्रोश के भीतर संवेदना। उनके संवाद केवल सुने नहीं जाते थे, भीतर ठहर जाते थे। कई बार उनके चेहरे का मौन ही पूरा संवाद बन जाता था।

पुरस्कारों और सम्मानों से परे उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उन्होंने दर्शकों को अभिनय की बनावट नहीं, जीवन की सच्चाई दिखाई। यही कारण है कि उनके किरदार फिल्म खत्म होने के बाद भी मन में चलते रहते हैं।

आज उनके जाने पर सिनेमा का पर्दा कुछ अधिक सूना लगता है। पर सच्ची कला मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होती। वह स्मृति बनकर पीढ़ियों के बीच अपना रास्ता खोजती है। नाना पाटेकर चले गए, लेकिन उनके किरदारों की आंखें, उनकी आवाज का कंपन और उनका सधा हुआ मौन हमारे बीच रहेगा।

नाना पाटेकर को *जन जन विचार* की विनम्र और अश्रुपूरित श्रद्धांजलि।

राजनीति में सेवा का अर्थ

राजनीति में सफलता केवल चुनाव जीतने से तय नहीं होती। असली कसौटी यह है कि नेता जनता के सुख–दुख से कितना जुड़ता है और सत्ता को सेवा का माध्यम कितना बना पाता है। नरेंद्र मोदी की राजनीतिक यात्रा को समझने के लिए 1987 की गुजरात की 'न्याय यात्रा' एक महत्वपूर्ण प्रसंग है।

उस समय गुजरात भीषण सूखे से जूझ रहा था। गांवों में पानी और चारे का संकट था, मजदूर राहत कार्यों में लगे थे, लेकिन मजदूरी के भुगतान और राहत राशि के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठ रहे थे। ऐसे समय में 'न्याय यात्रा' का उद्देश्य केवल राजनीतिक विरोध नहीं था। मजदूरों, किसानों और आदिवासियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, राहत कार्यों की वास्तविक स्थिति जानना और सरकारी व्यवस्था की कमियों को सामने लाना इसके प्रमुख उद्देश्य थे। इस यात्रा ने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश दिया–जनता को केवल भाषण नहीं, उसके अधिकारों की जानकारी और उसके हिस्से का लाभ चाहिए। सेवा के इसी भाव ने संगठन और समाज के बीच दूरी कम की। यही वह सोच थी, जिसने आगे चलकर मोदी की राजनीतिक शैली को प्रभावित किया। नरेंद्र मोदी की सफलता के समर्थक इसका श्रेय उनकी संगठन क्षमता, राजनीतिक रणनीति और प्रशासनिक शैली को देते हैं। आलोचक उनकी राजनीति के दूसरे पहलुओं पर सवाल उठाते हैं। लेकिन यह स्वीकार करना होगा कि जनसंपर्क और सेवा–भाव उनकी राजनीति का महत्वपूर्ण आधार रहा है।

एसआईआर पर हंगामा

...✍ उमेश चतुर्वेदी

विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ा हुआ है। विशेषकर विपक्षी दल जिस तरह से इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, उससे माहौल में एक भ्रम फैल रहा है। विपक्षी हंगामे और सवालों के चलते ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी है, जो मानने लगे हैं कि मतदाता सूची की जांच एक तरह से नागरिकता की जांच हो गई है। लोग एक बारगी वोटर न होने को बर्दाश्त कर भी लें, लेकिन कोई नहीं चाहेगा कि उसकी जन्मजात नागरिकता पर सवाल उठे या वह खतरे में पड़े। कहना न होगा कि विशेषकर पश्चिम बंगाल में हुए एसआईआर के बहाने विपक्ष यह भ्रम और डर–दोनों फैलाने में किंचित सफल रहा है। हालांकि यह भी सच है कि ऐसा भ्रम और डर सिर्फ पश्चिम बंगाल और बिहार के ही कुछ इलाकों में ही दिख रहा है। एसआईआर उत्तर प्रदेश में भी हुआ है और दिल्ली में भी जारी है। एसआईआर तमिलनाडु में भी हुआ है। लेकिन यहां के मतदाताओं के बीच ऐसा भ्रम और डर न के बराबर दिखा है।

ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर बिहार और पश्चिम बंगाल में ऐसा डर क्यों दिख रहा है? इसकी वजह है, वहां पिछले कुछ दशकों में बांग्लादेश से बढ़ी घुसपैठ। पश्चिम बंगाल में जब सत्ता में वाममोर्चा था, तब यही ममता बनर्जी वहां घुसपैठ के मुद्दे को उछालती रहती थीं और वाममोर्चे पर आरोप लगाती रहती थीं कि वह इसे बढ़ावा दे रहा है। ममता बनर्जी इस बहाने परोक्ष रूप से वाममोर्चा पर आरोप लगाती थीं कि मतदाता बने घुसपैठियों के ही सहारे वह पश्चिम बंगाल की सत्ता में काबिज है। बाद के दिनों में ये मतदाता ममता के समर्थक हो गए और ममता की सत्ता के आधार बनने लगे तो उन्हें भी यह मामला फिजूल का लगने लगा। बिहार का सीमांचल इलाका भी बांग्लादेशी घुसपैठ से प्रभावित रहा है। इसलिए वहां भी ऐसे सवाल और भ्रम उठ रहे हैं। चूंकि एसआईआर में ऐसे अवैध मतदाता ज्यादा सवालों के घेरे में हैं या फिर उनके नाम कट रहे हैं, इस वजह से इन्हीं राज्यों में यह मुद्दा कुछ ज्यादा तुर्श दिख रहा है।

मतदाता सूची में सुधार और उसमें चुनाव आयोग एवं मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर भी बड़े सवाल उठे हैं। सवाल यह भी है कि क्या एसआईआर को लेकर उठाए जा रहे सवाल असल में प्रक्रियात्मक और कानूनी हैं या इनके जरिए सिर्फ राजनीति हो रही है? पहले ही कहा जा चुका है कि एसआईआर को लेकर विपक्षी दलों की सबसे ज्यादा आपत्तियां बिहार और पश्चिम बंगाल से जुड़ी बताई जा रही हैं। कुछ राजनेताओं और दलों ने एसआईआर के आधार पर इन राज्यों के चुनावी परिणामों और मतदाता सूची की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। यहां ध्यान रखने की बात है कि एसआईआर केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी हुआ, लेकिन वहां बिहार या पश्चिम बंगाल की तरह इस पर सियासी विवाद नहीं हुआ। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि यदि कुछ राज्यों में एसआईआर को लेकर गंभीर आपत्ति नहीं है तो फिर एक या दो राज्यों में गंभीर आपत्तियां क्या राजनीतिक एजेंडे की वजह से तो नहीं उठाई जा रहीं? एसआईआर को देखने और समझने की एक ही कसौटी हर राज्य में क्यों नहीं लागू की जा रही है? इससे तो यही संकेत जाता है कि इसका सियासी विरोध सेलेक्टिव है और दोहरे मापदंड से भरा हुआ है।

क्या है एसआईआर की मानक प्रक्रिया?

एसआईआर को लेकर जारी बहस में बड़े पैमाने पर नाम हटाने, तकनीकी प्रणाली के इस्तेमाल और पारदर्शिता जैसे सवाल उठाए गए हैं। मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया निर्धारित कानूनी और प्रशासनिक चरणों के तहत होती है। नाम हटाने से पहले मतदाता को नोटिस जारी करने और उसकी आपत्तियों और तर्कों की सुनवाई की जाती है। इसके बाद आखिरी निर्णय संबंधित निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर होता है। इसलिए ड्राफ्ट मतदाता सूची में किसी मतदाता का नाम नहीं होना और अंतिम मतदाता सूची से नाम हट जाना, एक ही बात नहीं है। इसलिए जरूरी है कि दावे, ड्राफ्ट आंकड़े, आपत्तियों और अंतिम निर्णय, इन सभी चरणों को अलग–अलग समझा जाए। हर स्तर पर चूंकि आयोग ने पारदर्शी व्यवस्था अपना रखी है, इसे समझना हो तो अभी दिल्ली के किसी बीएलओ केंद्र का दौरा किया जा सकता है। दिल्ली में खूब नोटिस जारी किए गए हैं, उनके जवाब में लोग बीएलओ यानी बूथ स्तर के अधिकारी के पास पहुंच रहे हैं। लेकिन अफरातफरी, घबराहट या दहशत नहीं दिख रही। बीएलओ लोगों से जरूरी फॉर्म और प्रमाण ले रहे हैं। ज्यादातर नोटिस की वजह पूरा नाम ना होना, नाम की वर्तनी गलत होना, पिता या पति के नाम का पूरा न होना या फिर उनके नाम की वर्तनी में गड़बड़ी या कमी होना है। अधिकारियों का कहना है कि ईसीआईनेट का सॉफ्टवेयर मतदाता सूची के पहले से जारी नाम और आवेदन में कुछ भी गड़बड़ी पाता है तो वह नोटिस जेनरेट कर देता है। उदाहरण के लिए, पहले से किसी का नाम मतदाता सूची में सिर्फ रमेश दर्ज है, जबकि उसका पूरा नाम रमेश शर्मा है, या इसी तरह उसके पिता का पूरा नाम दर्ज नहीं है। लेकिन पहचान के दूसरे दस्तावेजों में उसका पूरा नाम दर्ज है। जब आयोग के अधिकारी ईसीआईनेट पर इसे लोड करते हैं तो सॉफ्टवेयर इस गड़बड़ी या बेमेल तथ्य को पकड़ता है। इसी तरह किसी का पता बदल गया है, जो पहले से दर्ज रिकॉर्ड से अलग है तो उसे भी नोटिस जा रही है। बस इन्हें प्रमाणित करना भर है। लेकिन राजनीतिक दल इसे या तो समझ नहीं रहे या फिर जानबूझकर नासमझी दिखा रहे हैं। वैसे भी इन प्रमाणों को घुसपैठिए या अवैध मतदाता साबित नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उनके नाम कट रहे हैं या काटे जाने की संभावना बन रही है।

संस्थाओं पर बहस हो, लेकिन तथ्यों के आधार पर

एसआईआर, निर्वाचन आयोग और न्यायपालिका पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक तो है, लेकिन आरोप और प्रमाण, ड्राफ्ट सूची और अंतिम सूची, याचिका और न्यायिक आदेश तथा राजनीतिक मांग और कानूनी कार्रवाई, के बीच समझदारी से अंतर बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। अव्वल तो मतदाता सूची की शुद्धता और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर बहस तथ्यों, कानून और निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। चुनाव आयोग बार–बार यह भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा है कि एसआईआर मतदाताओं को बेहतर सुविधा देने की व्यवस्था है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य है, कोई भी वैध और योग्य मतदाता छूटे नहीं। मोटे तौर पर एसआईआर का एक ही मकसद है, हर योग्य और वैध मतदाता को सूची में जोड़ना, दिए गए पते पर न रहे मतदाताओं और मृतकों का नाम सूची से हटाना। इसके साथ ही विदेशी और घुसपैठियों को मतदाता सूची से बाहर करना है। एक आरोप यह लग रहा है कि मतदाता सूची तैयार करने में ईसीआईनेट सॉफ्टवेयर की भूमिका बीएलओ और ईआरओ की तुलना में बढ़ गई है, जिसकी वजह से मतदाता सूची को फाइनल करने के ईआरओ के अधिकार दरकिनार हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ईसीआईनेट सिर्फ तकनीकी मंच है, जिसकी बुनियाद अधिकारियों द्वारा घर–घर से जुटाए आंकड़े हैं। नहीं भूलना चाहिए कि मतदाता सूची में किसी नाम को जोड़ने या उससे हटाने का निर्णय सिर्फ ईआरओ ही ले सकता है और वह भी जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 और मतदाता सूची पंजीयन नियम 1960 के तहत, नोटिस और सुनवाई के बाद ही ऐसा कर सकता है। कहना न होगा कि ऐसा ही हो रहा है। लेकिन राजनीति इसे देखने की बजाय अपने हिसाब से घटनाओं और कार्यों की व्याख्या कर रही है।



मतदाताओं के नाम जोड़ने का विशेष अभियान

पटना। बिहार में छूटे हुए और नए युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

अभियान के तहत बीएलओ घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे। पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए प्ररूप-6 भराया जाएगा। प्रशासन ने अभियान को एक महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा है। निर्वाचन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कोई भी पात्र मतदाता पंजीकरण से वंचित न रहे।

चार सौ कारोबारी कर विभाग की निगरानी में

नालंदा। जिले में करीब 400 कारोबारी राज्य कर विभाग की जांच के दायरे में आए हैं। विभाग को आशंका है कि इन कारोबारियों ने 2017-18 से कारोबार के अनुपात में पर्याप्त नकद जीएसटी जमा नहीं किया और इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए कर देनदारी पूरी दिखाई। प्रारंभिक जांच में करीब चार से साढ़े चार करोड़ रुपए की संभावित कर देनदारी सामने आई है। संबंधित कारोबारियों को नोटिस जारी कर 15 दिनों में जवाब देने और बकाया कर जमा करने को कहा गया है। जांच शुरू होने के बाद करीब 17 लाख रुपए नकद कर जमा भी कराया जा चुका है। जांच में दवा, कपड़ा, हार्डवेयर-सैनिटरी, लकड़ी-फर्नीचर, किराना और खाद्यान्न कारोबार शामिल हैं। विभाग खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड की जांच कर वास्तविक कर देनदारी तय करेगा। बकाया मिलने पर कर के साथ ब्याज और नियमानुसार जुर्माना भी वसूला जा सकता है।

दुर्गापूजा पर भागलपुर में सख्ती

जन जन विचार
...✍ भागलपुर

दुर्गापूजा के दौरान शांति, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए भागलपुर प्रशासन ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा और बिना लाइसेंस कोई जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाने पर भी रोक रहेगी।

बुधवार को जिलाधिकारी अलंकृता पांडे की अध्यक्षता में हुई जिला शांति समिति की बैठक में पूजा समितियों और प्रशासन के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने स्पष्ट किया कि विसर्जन जुलूस के लिए निर्धारित नियमों का पालन अनिवार्य होगा। संवेदनशील क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा और पंडालों के आसपास भी निगरानी बढ़ाई जाएगी।

पंडालों में सीसीटीवी और स्वयंसेवक अनिवार्य

बड़े पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ रात में कम से कम दो-तीन स्वयंसेवकों की मौजूदगी सुनिश्चित करने को कहा गया है। स्वयंसेवकों के पास पहचान पत्र या बैज होना जरूरी होगा। पंडालों में अग्नि सुरक्षा के लिए पर्याप्त मात्रा में बालू और पानी से भरे ड्रम रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।

प्रशासन ने पंडालों के आसपास ठेला-खोमचा लगाने से बचने को कहा है, ताकि अग्निशमन वाहन, एंबुलेंस और प्रशासनिक वाहनों के आवागमन में बाधा न आए। चिमकी लाइट कम से कम 16 फीट की ऊंचाई पर लगाने का सुझाव दिया गया है।

सफाई, रोशनी और यातायात पर भी नजर

पूजा स्थलों और विसर्जन मार्गों की सफाई, खराब सड़कों की मरम्मत, घाटों पर रोशनी और बैरिकेडिंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम को पूजा स्थलों पर चूना और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव तथा रात में कचरा उठाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है।

भीड़ को देखते हुए जरूरत पड़ने पर शहर के कुछ हिस्सों में एकतरफा यातायात व्यवस्था लागू की जा सकती है। यातायात में बदलाव की जानकारी लोगों को माध्यमों के जरिए दी जाएगी।

छोटी घटना को गंभीर होने से रोकने की अपील

पुलिस प्रशासन ने पूजा समितियों और आम लोगों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अप्रिय घटना की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की है। प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि त्योहार के दौरान नियमों का पालन, संयम और सहयोग ही सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण आयोजन की सबसे बड़ी गारंटी है।

पृष्ठ 1 का शेषांश...

राहुल की 'धप्पा' राजनीति

प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने निर्वाचन आयोग की ओर बढ़ रहे विपक्षी नेताओं को रोकने के लिए भारी बैरिकेडिंग कर रखी थी। पुलिस की तैयारी स्पष्ट थी- मार्च को आगे बढ़ने से रोकना और नेताओं को हिरासत में लेकर प्रदर्शन समाप्त करना।

राहुल गांधी ने पहले बैरिकेड पर चढ़कर तिरंगा लहराया। इसके बाद नेताओं को बसों में बैठाया जाने लगा। पहली नजर में लगा कि प्रदर्शन खत्म हो गया। लेकिन यहीं से कहानी बदली।

पुलिस ने बस देखी, राहुल ने रास्ता बदल दिया

राहुल गांधी बस में चढ़ने वाले थे। तभी उन्होंने प्रियंका गांधी को इशारा किया। दोनों अचानक बस से अलग हुए और आकाशवाणी भवन की ओर बढ़ गए। कुछ ही देर में वे परिसर में पहुंच गए।

प्रशासन के लिए यह अप्रत्याशित स्थिति थी। सुरक्षा कर्मियों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन गांधी भाई-बहन परिसर में दाखिल हो गए। इसके बाद कांग्रेस के दूसरे नेता भी वहां पहुंचने लगे। निर्वाचन सदन की ओर जाने वाले संभावित रास्ते को पुलिस ने बंद कर दिया, लेकिन तब तक विरोध का नया मंच तैयार हो चुका था।

राहुल और प्रियंका गांधी परिसर में एक पेड़ के नीचे बैठ गए। कांग्रेस नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। धरना घंटों चला और रात तक पुलिस तथा प्रदर्शनकारियों के बीच गतिरोध बना रहा।

आखिरकार रात करीब आठ बजे परिसर खाली कराया गया। राहुल गांधी और अन्य नेताओं को हिरासत में लेकर किंग्सवे कैंप थाने ले जाया गया और बाद में रिहा कर दिया गया।

लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की सबसे महत्वपूर्ण बात हिरासत नहीं थी। महत्वपूर्ण यह था कि प्रशासन ने जिस विरोध को नियंत्रित करने की तैयारी की थी, राहुल ने उसी घेरे के भीतर उसका नया मंच तैयार कर दिया।

जुलाई में प्रधानमंत्री आवास के पास अचानक पहुंचना : 21 जुलाई को संसद की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के अगले दिन राहुल गांधी और कांग्रेस सांसदों का एक दल अचानक प्रधानमंत्री आवास के पास पहुंच गया था। कांग्रेस के कई सांसदों को भी अंतिम क्षणों तक वास्तविक योजना की जानकारी नहीं थी। नेताओं को पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर बुलाया गया था। इसके बाद अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकारी आवास की ओर मार्च शुरू हुआ। प्रशासन के लिए यह भी अप्रत्याशित स्थिति थी। पुलिस ने राहुल गांधी को वहां से हटाया। धक्का-मुक्की के दौरान उनकी नाक पर चोट लगने की बात भी सामने आई। यहां भी राहुल ने एक बात साबित करने की कोशिश की-विरोध का प्रभाव केवल उसके आकार से नहीं, उसकी अप्रत्याशितता से भी पैदा किया जा सकता है।

अगस्त में थाना बना आंदोलन का केंद्र : 21 अगस्त को राहुल गांधी का तीसरा प्रयोग सामने आया। वे छात्र साहिल लोचब के साथ संसद मार्ग पुलिस थाने पहुंचे। साहिल ने आरोप लगाया था कि 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान उसे पैलेट गन से चोट लगी थी। राहुल ने मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। जब तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो राहुल थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। कुछ ही देर में प्रियंका गांधी और कांग्रेस के अन्य नेता भी वहां पहुंच गए। सुरक्षा बढ़ाई गई और फिर वही स्थिति बनी-प्रशासन के सामने ऐसा विरोध, जिसका अंत तत्काल दिखाई नहीं दे रहा था। कई घंटे बाद प्राथमिकी दर्ज की गई और गतिरोध समाप्त हुआ।

तीन घटनाओं में छिपा एक राजनीतिक पैटर्न : इन तीनों घटनाओं को अलग-अलग देखा जाए तो ये सामान्य राजनीतिक विरोध लग सकते हैं। लेकिन इन्हें एक साथ देखें तो राहुल गांधी की रणनीति में एक स्पष्ट बदलाव दिखाई देता है।

पहला—अचानक निर्णय।

दूसरा—प्रशासन की तैयारियों के बीच नया रास्ता।

तीसरा—विरोध को लंबे समय तक दृश्य बनाए रखना।

इस रणनीति का एक और पहलू है—मीडिया और सामाजिक माध्यमों पर तुरंत असर। आकाशवाणी भवन की घटना इसका उदाहरण है। कांग्रेस ने राहुल के अचानक रास्ता बदलने का वीडियो साझा करते हुए 'धप्पा' शब्द का इस्तेमाल किया। देखते ही देखते यह प्रदर्शन की पहचान बन गया।

क्या यह राजनीति का नया 'राहुल मॉडल' है?

राहुल गांधी के समर्थक इसे सत्ता के खिलाफ निर्भीक सड़क-राजनीति मान सकते हैं। उनके आलोचक इसे राजनीतिक नाटकीयता और प्रशासन को जानबूझकर चुनौती देने की रणनीति कह सकते हैं। दोनों पक्षों के अपने तर्क हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि राहुल गांधी की शैली में बदलाव आया है।

वे अब केवल संसद में सरकार को घेरने, प्रेस वार्ता करने या सामाजिक माध्यमों पर मुद्दा उठाने तक सीमित नहीं दिखना चाहते। वे सड़क पर मौजूदगी, अचानक विरोध और प्रत्यक्ष टकराव को भी अपने राजनीतिक अभियान का हिस्सा बना रहे हैं। यही वजह है कि अब सवाल केवल यह नहीं है कि राहुल अगला विरोध कब करेंगे। बड़ा सवाल यह है कि वे अगली बार विरोध का मंच कहां बनाएंगे।

'धप्पा' का असली अर्थ : राजनीति में अप्रत्याशितता दोधारी तलवार होती है। एक ओर यह विरोध को सुर्खियों में ला सकती है, प्रशासन को रक्षात्मक कर सकती है और कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा कर सकती है। दूसरी ओर, यदि यही रणनीति बार-बार दोहराई जाए तो इसका असर धीरे-धीरे कम भी हो सकता है। राहुल गांधी के सामने अब चुनौती यही है-'धप्पा' को केवल अचानक किए गए प्रदर्शन से आगे ले जाकर उसे स्थायी राजनीतिक संदेश में बदलना। क्योंकि सरकार को चौंका देना एक बात है, लेकिन मतदाता को अपने पक्ष में मोड़ना दूसरी।

आकाशवाणी भवन का घटनाक्रम राहुल की इस नई राजनीतिक शैली का तीसरा बड़ा उदाहरण है। अब निगाहें इस पर रहेंगी कि अगली बार जब प्रशासन को लगेगा कि राहुल गांधी का रास्ता तय है, तब क्या वे फिर कोई ऐसा मोड़ लेंगे जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होगी?

यही राहुल की 'धप्पा' राजनीति की असली परीक्षा होगी।

तीन महीने में पैसा दोगुना करने का जाल, सीए गिरफ्तार

जन जन विचार
...✍ पटना

तीन से आठ महीने में निवेश की रकम दोगुनी करने का लालच, आलीशान कार्यालय, नोट गिनने की मशीनें और मुनाफे के शुरुआती भुगतान-इन्हीं तरीकों के सहारे लोगों को निवेश के लिए आकर्षित करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट श्रीधर पाठक को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, उसके खिलाफ निवेशकों से करीब 100 करोड़ रुपए की कथित ठगी के आरोप सामने आए हैं। करीब दो साल से फरार चल रहे पाठक को पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया।

पुलिस जांच में सामने आया है कि पाठक ने 'न्यू एरा ट्रेडिंग हाउस' के नाम से कारोबार खड़ा किया था। उसके लिए कर्मचारी और फील्ड एजेंट लोगों से संपर्क करते तथा निवेश के लिए तैयार करते थे। जान-पहचान के लोगों के माध्यम से निवेशकों की एक श्रृंखला बनाई गई। आरोप है कि निवेशकों को तीन से छह महीने में रकम दोगुनी करने और कुछ योजनाओं में मासिक 10 प्रतिशत तक मुनाफे का भरोसा दिया जाता था।

दफ्तर की चमक से पैदा किया भरोसा

पटना के दीघा इलाके में बने कार्यालय में चार नोट गिनने वाली मशीनें होने और कर्मचारियों की मौजूदगी ने निवेशकों के बीच कारोबारी गतिविधि का भरोसा पैदा किया। बाद में बोधगया में भी कार्यालय खोला गया। पुलिस के अनुसार, इस नेटवर्क में पाठक के साथ कई अन्य लोग भी जुड़े थे और निवेश जुटाने वालों को कमीशन दिया जाता था।

शुरुआत में कुछ निवेशकों को मुनाफा मिलने से भरोसा और बढ़ा। इसके बाद कई लोगों ने अपनी जमा पूंजी, सेवानिवृत्ति की रकम और कारोबार का पैसा तक निवेश कर दिया। जब भुगतान का समय आया तो कथित तौर पर कंपनी और संचालक से संपर्क टूट गया।

करोड़ों गंवाने का दावा

पीड़ितों में शिक्षक, कारोबारी और अन्य लोग शामिल हैं। कुछ निवेशकों ने लाखों तो कुछ ने करोड़ों रुपए लगाए। एक निवेशक ने 1.72 करोड़ रुपए, जबकि दूसरे ने करीब 2 करोड़ रुपए लगाने का दावा किया है। एक सेवानिवृत्त शिक्षक ने अपनी बेटी की शादी के लिए जमा रकम निवेश करने की बात कही। भुगतान नहीं होने के बाद कई परिवार आर्थिक संकट में पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक, मामले में लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। कोतवाली पुलिस ने आर्थिक अपराध इकाई और आयकर विभाग की मदद से वित्तीय लेनदेन की जांच की प्रक्रिया शुरू की है।

पैसा कहां गया, नेटवर्क में कौन-कौन?

अब जांच का सबसे बड़ा सवाल यही है कि निवेशकों से जुटाई गई कथित करोड़ों रुपए की रकम कहां गई। पुलिस बैंक खातों, लेनदेन, निवेश दस्तावेजों और संपत्तियों की पड़ताल कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल थे।

यह मामला केवल कथित ठगी की रकम का नहीं, बल्कि उस भरोसे का भी है जिसे चमकदार कार्यालय, शुरुआती मुनाफे और जान-पहचान के नेटवर्क के जरिए बनाया गया। असामान्य रूप से ऊंचे और जल्दी मिलने वाले रिटर्न का लालच निवेशकों के लिए हमेशा गंभीर चेतावनी है। पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही पूरे नेटवर्क और वास्तविक वित्तीय नुकसान की तस्वीर स्पष्ट होगी।

आपके गांव-घर की खबर

बिहार के मजदूरों को रतलाम में बंधक बनाने का आरोप

गोपालगंज/रतलाम। लखनऊ में नौकरी और बेहतर मजदूरी का झांसा देकर गोपालगंज के करीब एक दर्जन मजदूरों को मध्य प्रदेश के रतलाम ले जाकर बंधक बनाकर काम कराने का मामला सामने आया है। जावड़ा गांव की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर फंसे मजदूरों ने वीडियो जारी कर मदद की गुहार लगाई है। मजदूरों का आरोप है कि उनसे जबरन सरिया बांधने समेत भारी काम कराया जा रहा है और मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया। घर लौटने या काम से इनकार करने पर जान से मारने की धमकी देने की भी बात कही गई है। मजदूरों के अनुसार, डोमाहाता गांव के एजेंट धर्मेंद्र यादव ने उन्हें लखनऊ में काम दिलाने का भरोसा देकर बुलाया था, लेकिन बाद में रतलाम भेज दिया। वीडियो सामने आने के बाद परिजनों में चिंता बढ़ गई है। मामले में बिहार भवन के संयुक्त श्रम आयुक्त कुमार दिग्विजय ने रतलाम के जिलाधिकारी को पत्र भेजकर पुलिस बल के साथ तत्काल रेस्क्यू की मांग की है। बिहार भवन ने मजदूरों को मुक्त कराकर भोजन, आश्रय और चिकित्सा सुविधा देने, बकाया मजदूरी दिलाने और सुरक्षित गोपालगंज भेजने की मांग की है। एजेंट और संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग की गई है।

प्रेम प्रसंग में 14 साल के छात्र की हत्या

मुजफ्फरपुर। कटरा थाना क्षेत्र से लापता 14 वर्षीय छात्र की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी की बेटी से प्रेम प्रसंग के चलते छात्र की गला दबाकर हत्या की गई और शव पोखर में फेंक दिया गया। मामले में एक दंपती और उनकी नाबालिग बेटी को पकड़ा गया है। छात्र की मां रंजू देवी ने 5 अक्टूबर को उसके लापता होने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया गया कि छात्र गेहूं पिसाने के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। तलाश के दौरान मंगलवार को देवगन एनएच के पास एक तालाब से उसका शव बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपी मदन दास ने छात्र के अपनी बेटी के संपर्क में होने की बात बताई।

मुंगेर में मां दुर्गा का पंडाल बना रहे 75 मुस्लिम कारीगर

जन जन विचार
...✍ मुंगेर



सिर पर टोपी, हाथों में औजार और सामने मां दुर्गा का भव्य दरबार...मुंगेर के कल्याणपुर में इन दिनों यह दृश्य लोगों का ध्यान खींच रहा है। जिस पंडाल में मां दुर्गा विराजेंगी, उसकी एक-एक परत करीब 75 मुस्लिम कारीगरों के हाथों से आकार ले रही है। झारखंड के गिरिडीह से आए ये कारीगर पिछले ढाई महीने से दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। उनके हाथ बांस, कपड़े और रस्सियों को जोड़कर ऐसा ढांचा खड़ा कर रहे हैं, जो तैयार होने के बाद मलेशिया के प्रसिद्ध पेट्रोनास ट्विन टावर की झलक देगा।

करीब 170 फीट ऊंचा और 150 फीट चौड़ा यह पंडाल इस बार मुंगेर की दुर्गापूजा का बड़ा आकर्षण बनने जा रहा है। दोनों टावरों को जोड़ने वाला स्काई ब्रिज भी बनाया जा रहा है। पंडाल के निर्माण में हजारों बांस और बड़ी मात्रा में कपड़ा, रस्सी तथा अन्य सामग्री इस्तेमाल की जा रही है।

लेकिन इस पंडाल की असली कहानी इसकी ऊंचाई से भी बड़ी है। मां दुर्गा के स्वागत के लिए जिस भव्य संरचना को तैयार किया जा रहा है, उसके पीछे अलग-अलग धार्मिक पहचान वाले कारीगरों की साझा मेहनत है। करीब 12 वर्षों से ये कारीगर इसी पूजा समिति के लिए पंडाल तैयार करते आ रहे हैं। हर वर्ष नई थीम, नई चुनौती और वही हुनर-यही इस आयोजन की पहचान बन चुका है।

मलेशिया के ट्विन टावर की तर्ज पर भव्यता

पूजा समिति के आयोजक डॉ. नीतिश चंद्र दुबे के अनुसार, मलेशिया यात्रा के दौरान उन्होंने ट्विन टावर देखा था। उनका विचार था कि जिन लोगों के लिए विदेश जाकर ऐसी इमारत देखना संभव नहीं, उन्हें उसकी झलक अपने शहर में ही दिखाई जाए। इससे पहले यहां बुर्ज खलीफा, थाईलैंड के अरुण मंदिर और जयपुर के हवामहल जैसी थीम पर भी पंडाल बनाए जा चुके हैं।

दुर्गापूजा के साथ दिखेगी साझा मेहनत की तस्वीर

इस बार पंडाल परिसर को झरना और घंटियों की थीम पर सजाया जा रहा है। करीब 10 हजार घंटियां लगाए जाने की तैयारी है। लेजर प्रकाश व्यवस्था के साथ सुरक्षा के लिए कैमरे भी लगाए जाएंगे। आयोजन समिति श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए विशेष इंतजाम कर रही है।

मुंगेर का यह पंडाल इसलिए भी खास है कि यहां उत्सव की भव्यता केवल बांस, कपड़े और रोशनी से नहीं बन रही, बल्कि उन हाथों से बन रही है जिनके लिए कारीगरी ही सबसे बड़ी पहचान है। मां दुर्गा के स्वागत में जुटे ये 75 कारीगर अपने हुनर से एक ऐसी तस्वीर गढ़ रहे हैं, जिसमें पर्व की आस्था के साथ मेहनत और सामाजिक मेल-जोल की झलक भी दिखाई देती है।

नेट में वैभव का तूफान, क्या मिलेगा मौका?

कपिल देव की वैभव सूर्यवंशी को सलाह: अगले दो साल रन से ज्यादा जरूरी होगी जीवनशैली

जन जन विचार
...✍ रांची

मैदान पर मुकाबला शुरू होने से पहले ही भारतीय टीम के अभ्यास सत्र ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है-क्या 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को दूसरे टी-20 में अंतिम एकादश में जगह मिलेगी? रांची में अभ्यास के दौरान बिहार के इस युवा बल्लेबाज ने लगातार आक्रामक शॉट लगाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। दर्शकों और मीडिया की निगाहें लंबे समय तक नेट पर जमी रहीं। हालांकि टीम प्रबंधन की ओर से अभी अंतिम एकादश को लेकर कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिया गया है।

वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी-20 से पहले भारतीय टीम ने करीब दो घंटे अभ्यास किया। इस दौरान ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी दोनों ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की। वैभव की खास चर्चा इसलिए हुई क्योंकि उनके शॉट्स में उम्र से कहीं अधिक आत्मविश्वास और आक्रामकता दिखाई दी।

सैमसन ने भी जमाए शॉट

वैभव के प्रदर्शन के बीच संजू सैमसन ने भी नेट्स पर बल्लेबाजी की। उन्होंने शुरुआत में धैर्य दिखाया और बाद में कुछ आकर्षक शॉट लगाए। ऐसे में वैभव को मौका मिलने की चर्चा के बीच सैमसन को बाहर किए जाने की संभावना अभी केवल अटकल है। अंतिम फैसला टीम प्रबंधन ही करेगा।

ईशान के लिए घरेलू मैदान पर बड़ा मौका

रांची का मुकाबला ईशान किशन के लिए खास है। झारखंड के कप्तान रह चुके ईशान ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय टी-20 टीम में वापसी की है। अभ्यास में उन्होंने स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ कई बड़े शॉट लगाए। रवि बिश्नोई, नमन धीर और अभिषेक शर्मा ने उन्हें गेंदबाजी की।

वैभव पर सबकी निगाहें

भारतीय क्रिकेट में कम उम्र में अपनी पहचान बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी के लिए रांची का अभ्यास सत्र एक और बड़ा मंच साबित हुआ। सहायक कोच सितांशु कोटक ने ईशान की बल्लेबाजी की परिपक्वता की तारीफ की और कहा कि वह अब परिस्थितियों के अनुसार बल्लेबाजी करते हैं।

पहले टी-20 में जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी के बीच तेज गेंदबाजी में संघर्ष दिखा था। मयंक यादव को भी अभ्यास से आराम दिया गया। कप्तान श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव वैकल्पिक अभ्यास सत्र में नहीं आए।

अब असली सवाल रांची में यही है- नेट्स में बल्ले से हलचल मचाने वाले वैभव को क्या मैदान पर उतरने का मौका मिलेगा, या सैमसन ही टीम की पसंद बने रहेंगे? इसका जवाब टॉस के समय ही साफ होगा।

नई दिल्ली। *15 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की दहलीज पर पहुंचकर सुर्खियां बटोर रहे वैभव सूर्यवंशी को लेकर भारतीय क्रिकेट के महान कप्तान कपिल देव ने ऐसी बात कही है, जो युवा बल्लेबाज के लिए चेतावनी भी है और सलाह भी। कपिल का मानना है कि वैभव में विश्व क्रिकेट पर लंबे समय तक राज करने की पूरी क्षमता है, लेकिन उनकी असली परीक्षा मैदान से बाहर होगी।*

कपिल देव ने वैभव की तुलना पूर्व भारतीय बल्लेबाज विनोद कांबली से करते हुए कहा कि क्रिकेट में प्रतिभा की कमी नहीं होती, लेकिन हर प्रतिभाशाली खिलाड़ी लंबा सफर तय नहीं कर पाता। उनके मुताबिक वैभव अभी सिर्फ 15 वर्ष के हैं, इसलिए उनके भविष्य को लेकर जल्द निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा।



कपिल ने कहा कि वैभव को कम से कम दो-तीन वर्ष का समय दिया जाना चाहिए। इस दौरान यह देखना अधिक महत्वपूर्ण होगा कि वह बढ़ती लोकप्रियता, पैसा और बदलती जीवनशैली को किस तरह संभालते हैं। उनके अनुसार केवल रन और रिकॉर्ड यह तय नहीं करते कि कोई खिलाड़ी महान करियर बनाएगा या नहीं।

क्षमता है, लेकिन अभी बहुत जल्दी है

कपिल देव ने कहा कि वैभव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करने की क्षमता जरूर है, लेकिन क्रिकेट में ऐसे कई खिलाड़ी आए हैं जिन्होंने शुरुआत में अपनी प्रतिभा से सबको प्रभावित किया और बाद में कहीं खो गए। उन्होंने विनोद कांबली का उदाहरण देते हुए इसी खतरे की ओर इशारा किया। उनका कहना है कि आने वाले दो वर्षों में वैभव का व्यवहार, अनुशासन और खेल के प्रति गंभीरता उनके प्रदर्शन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। जैसे-जैसे पैसा और प्रसिद्धि बढ़ेगी, उनकी जीवनशैली और सोच में भी बदलाव आएगा। इसी दौर में पता चलेगा कि वह सफलता को किस तरह संभालते हैं।

वैभव के सामने बड़ी चुनौती

वैभव सूर्यवंशी ने कम उम्र में ही अपनी बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत का ध्यान खींचा है। हालांकि भारतीय टीम में अनुभवी और स्थापित खिलाड़ियों की मौजूदगी के कारण उन्हें लगातार अंतिम एकादश में जगह नहीं मिल रही है। टीम के साथ रहकर उन्हें वरिष्ठ खिलाड़ियों से सीखने का अवसर मिल रहा है। कपिल देव की टिप्पणी का मूल संदेश यही है कि वैभव की प्रतिभा पर सवाल नहीं, बल्कि उसे संभालने की क्षमता पर नजर जरूरी है।

85 पदक, 21 स्वर्ण : पीएम मोदी से मिलेंगे एशियाई खेलों के सितारे

जन जन विचार
...✍ नई दिल्ली

एशियाई खेलों में देश का गौरव बढ़ाने वाले भारतीय खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अक्टूबर को मुलाकात करेंगे। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास पर होने वाली इस मुलाकात में एशियाई खेलों के सभी प्रमुख पदक विजेता शामिल होंगे।

आइची-नागोया में आयोजित एशियाई खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक अपने नाम किए। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। इस प्रदर्शन के साथ भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा।



भारतीय खिलाड़ियों ने तीरंदाजी, मुक्केबाजी, निशानेबाजी, हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती, कबड्डी, एथलेटिक्स और गोल्फ समेत कई खेलों में देश का मान बढ़ाया। तीरंदाजों ने पांच स्वर्ण सहित नौ पदक जीते, जबकि भारतीय मुक्केबाजों ने तीन स्वर्ण और तीन कांस्य सहित छह पदक हासिल किए।

टीम स्पर्धाओं में भी भारत का प्रदर्शन विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। क्रिकेट में भारतीय महिला और पुरुष दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। हॉकी और कबड्डी में भी भारत की महिला और पुरुष दोनों टीमें चैंपियन बनीं।

प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात करते रहे हैं। इससे पहले 9 अगस्त को उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के भारतीय पदक विजेताओं से अपने आवास पर मुलाकात की थी।

एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धि ने एक बार फिर यह साबित किया है कि देश का खेल दायरा लगातार व्यापक हो रहा है और कई खेलों में भारत अब पदक के मजबूत दावेदार के रूप में उभर रहा है।

नवरात्र :नौ रूपों में एक शक्ति, नौ संदेशों में पूरा जीवन

जन जन विचार
...✍ धर्म डेस्क

जब शरद ऋतु की पहली ठंडी हवा धरती को छूती है, आकाश निर्मल होने लगता है और वातावरण में उत्सव की आहट सुनाई देने लगती है, तब भारतीय संस्कृति में शक्ति की आराधना का पर्व आकार लेने लगता है। घरों में कलश स्थापित होते हैं, मंदिरों में घंटे गूंजते हैं और नौ दिनों तक मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की उपासना होती है।

शारदीय नवरात्र केवल देवी की पूजा के नौ दिन नहीं हैं। यह अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के नौ अवसर हैं।

मां दुर्गा के नौ रूपों में कहीं बेटी का रूप है, कहीं तपस्या है, कहीं मातृत्व है, कहीं रौद्रता है तो कहीं करुणा और शांति। इन सभी रूपों को एक साथ देखें तो वे जीवन का ऐसा दर्शन सामने रखते हैं, जिसमें मनुष्य को मजबूत भी होना है और संवेदनशील भी, संघर्ष करना है और संयम भी रखना है।

प्रथम दिन : मां शैलपुत्री

जहां से शुरू होती है शक्ति की यात्रा

नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। वे वृषभ पर आरूढ़ हैं और उनके हाथों में त्रिशूल तथा कमल सुशोभित हैं। पर्वत स्थिरता का प्रतीक है। इसलिए शैलपुत्री का संदेश भी यही है कि किसी भी बड़ी यात्रा की शुरुआत मजबूत संकल्प से होती है।

आज जब जीवन लगातार बदलती परिस्थितियों और अनिश्चितताओं से घिरा है, तब यह स्वरूप याद दिलाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, जिसके भीतर स्थिरता है, वही लंबे संघर्ष में टिक सकता है।

द्वितीय दिन : मां ब्रह्मचारिणी

सफलता का दूसरा नाम है तप

दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। हाथों में जपमाला और कमंडल धारण किए देवी का यह स्वरूप तप, त्याग, धैर्य और संयम का प्रतीक माना जाता है।

इच्छा करना आसान है, लेकिन इच्छा को लक्ष्य में बदलने के लिए तप चाहिए। रास्ते में थकान आएगी, असफलता मिलेगी, कई बार अकेलापन भी महसूस होगा—लेकिन जो अपने उद्देश्य से नहीं हटता, वही अंततः मंजिल तक पहुंचता है। ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं कि धैर्य भी एक साधना है।

तृतीय दिन : मां चंद्रघंटा

शक्ति में शांति, साहस में संतुलन

तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की आराधना होती है। मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली देवी का स्वरूप शौर्य और सौम्यता का अद्भुत संतुलन प्रस्तुत करता है।

जीवन में संघर्ष अपरिहार्य है, लेकिन हर संघर्ष क्रोध से नहीं जीता जा सकता। कई बार सबसे बड़ी शक्ति वही होती है जो कठिन परिस्थिति में भी मन को शांत रख सके।

चंद्रघंटा का संदेश है-साहसी बनिए, लेकिन विवेक को पीछे मत छोड़िए।



चतुर्थ दिन : मां कूष्मांडा

अंधकार में भी सृजन की संभावना

चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा होती है। धार्मिक परंपरा में उन्हें सृष्टि की आदिशक्ति से जोड़ा जाता है।

उनका स्वरूप हमें सृजन की शक्ति का स्मरण कराता है। जीवन में ऐसा समय भी आता है जब सब कुछ समाप्त होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन वहीं से नई शुरुआत की संभावना भी जन्म लेती है।

एक विचार, एक प्रयास, एक छोटा-सा कदम-कभी-कभी यही अंधकार में प्रकाश की पहली किरण बन जाता है। कूष्मांडा का संदेश है-परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों, सृजन की शक्ति को मरने मत दीजिए।

पंचम दिन : मां स्कंदमाता

ममता भी शक्ति है

पांचवें दिन मां स्कंदमाता की आराधना होती है। वे अपनी गोद में बाल रूप में भगवान कार्तिकेय को धारण किए दिखाई देती हैं।

देवी का यह रूप शक्ति की एक ऐसी तस्वीर सामने रखता है, जिसे अक्सर कम आंका जाता है-ममता।

किसी को जन्म देना ही मातृत्व नहीं है। किसी को संभालना, उसके डर में उसके साथ खड़ा होना, गिरने पर उठाना और बिना किसी स्वार्थ के सुरक्षा देना भी शक्ति है।

स्कंदमाता का स्वरूप बताता है कि संसार केवल पराक्रम से नहीं, करुणा और संरक्षण से भी चलता है।

षष्ठम दिन : मां कात्यायनी

अन्याय के सामने खड़े होने का साहस

छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। उनका स्वरूप शक्ति, साहस और अधर्म के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक माना जाता है।

हर युग में अन्याय के सामने खड़ा होना कठिन रहा है। गलत के साथ चलना आसान हो सकता है, लेकिन सही के लिए आवाज उठाने में साहस चाहिए।

कात्यायनी का संदेश स्पष्ट है-जहां अन्याय हो, वहां मौन हमेशा समाधान नहीं होता।

यह शक्ति केवल युद्ध की शक्ति नहीं, बल्कि अपने अधिकार, सम्मान और सत्य के लिए खड़े होने की शक्ति है।

सप्तम दिन : मां कालरात्रि

सबसे बड़ी लड़ाई अपने भय से

सप्तमी को मां कालरात्रि की पूजा होती है। उनका स्वरूप नवरात्र के सबसे उग्र रूपों में माना जाता है। लेकिन इसी उग्रता के भीतर भय से मुक्ति का संदेश छिपा है।

मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कई बार बाहर नहीं, उसके भीतर होता है-असफलता का भय, भविष्य का भय, समाज का भय और अपने निर्णयों का भय।

कालरात्रि का स्वरूप कहता है-भय से भागने पर वह बढ़ता है, उसका सामना करने पर वह छोटा पड़ने लगता है।

इसलिए उनका रौद्र रूप विनाश से अधिक निर्भयता का प्रतीक बन जाता है।

अष्टम दिन : मां महागौरी

शक्ति के बाद आती है शांति

अष्टमी के दिन मां महागौरी की आराधना की जाती है। उनका स्वरूप शांति, पवित्रता और निर्मलता से जुड़ा है।

नवरात्र की यात्रा यहां एक महत्वपूर्ण संदेश देती है-केवल शक्तिशाली होना पर्याप्त नहीं। शक्ति के साथ मन की निर्मलता भी चाहिए।

आज की भागदौड़ में मनुष्य बाहर से बहुत कुछ हासिल कर सकता है, लेकिन यदि भीतर शांति नहीं है तो उपलब्धियां भी अधूरी रह जाती हैं।

महागौरी हमें भीतर लौटने और स्वयं को निर्मल करने की प्रेरणा देती हैं।

नवम दिन : मां सिद्धिदात्री

साधना का अंतिम पड़ाव-पूर्णता

नवरात्र के अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। उन्हें सिद्धियों की दात्री और साधना की पूर्णता का प्रतीक माना जाता है।

लेकिन पूर्णता का अर्थ केवल उपलब्धि नहीं है। सच्ची पूर्णता तब है जब ज्ञान के साथ विनम्रता हो, शक्ति के साथ करुणा हो और सफलता के साथ जिम्मेदारी का बोध हो।

सिद्धिदात्री का संदेश है कि मनुष्य की यात्रा केवल बाहर की दुनिया जीतने की नहीं, अपने भीतर को समझने की भी है।

नौ देवियां, नौ जीवन-मंत्र

शैलपुत्री हमें दृढ़ता देती हैं।
ब्रह्मचारिणी संयम सिखाती हैं।
चंद्रघंटा साहस और संतुलन देती हैं।
कूष्मांडा सृजन की प्रेरणा देती हैं।
स्कंदमाता ममता और संरक्षण का अर्थ समझाती हैं।
कात्यायनी अन्याय के विरुद्ध खड़े होना सिखाती हैं।
कालरात्रि भय पर विजय का संदेश देती हैं।
महागौरी शांति और निर्मलता की राह दिखाती हैं।
सिद्धिदात्री ज्ञान और पूर्णता की ओर ले जाती हैं।

यही नवरात्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है-देवी के नौ रूप अलग दिखाई देते हैं, लेकिन शक्ति एक ही है।

वह शक्ति कभी बेटी बनकर घर आती है, कभी मां बनकर जीवन संभालती है, कभी योद्धा बनकर अन्याय से लड़ती है और कभी करुणा बनकर किसी टूटे हुए मन को सहारा देती है।

इसलिए नवरात्र में जब हम मां के सामने दीप जलाएं, तो केवल मनोकामना न मांगें। अपने भीतर भी एक दीप जलाने का संकल्प लें-अंधकार के विरुद्ध, भय के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध और सबसे बढ़कर अपने भीतर की कमजोरी के विरुद्ध।

क्योंकि देवी की सच्ची आराधना केवल मंदिर में सिर झुकाने में नहीं, उनके गुणों को अपने जीवन में उतारने में है।

यही शारदीय नवरात्र का संदेश है-

शक्ति बाहर कहीं नहीं, वह हमारे भीतर भी है। जरूरत केवल उसे पहचानने की है।



ৰাইজৰ কথা ৰাইজৰ মাজলৈ

সাপ্তাহিক

জন জন বিচাৰ

Guwahati, 9 October, 2026 Friday :: শুক্রবাৰ, আহিন, কৃষ্ণ পক্ষ, চতুর্দশী, শকাব্দ ১৯৪৮

ইউপিআইত মাচুলৰ সিদ্ধান্ত পিছুৱাব পাৰে কেন্দ্রই

১৫ অক্টোবৰৰ পৰা ০.৪ শতাংশ মার্চেণ্ট মাচুলৰ নিয়ম কার্যকৰী হোৱাৰ কথা; উৎসৱৰ বতৰত লেনদেন বিনামূলীয়াকৈ ৰখাৰ চিন্তা

জন জন বিচাৰ
...নতুন দিল্লী

ডিজিটেল লেনদেনৰ ক্ষেত্রত দেশবাসীৰ বাবে স্বস্তিৰ খবৰ আহিব পাৰে। ইউপিআইৰ জৰিয়তে কৰা ২,০০০ টকাৰ অধিক মূল্যৰ লেনদেনত মার্চেণ্ট মাচুল আৰোপৰ প্রস্তাৱিত নিয়ম ১৫ অক্টোবৰৰ পৰা কার্যকৰী কৰাৰ পৰিৱর্তে অহা বছৰৰ ১ জানুৱাৰীলৈ পিছুৱাই দিয়াৰ কথা চৰকাৰে বিবেচনা কৰা বুলি সূত্রৰ উদ্ধৃতিৰে প্রকাশ পাইছে।

এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হোৱা নাই যদিও উৎসৱৰ বতৰত দোকানী, ব্যৱসায়ী আৰু ডিজিটেল পেমেণ্ট সেৱা প্রদানকাৰীসকলৰ ওপৰত অতিৰিক্ত আর্থিক বোজা নপৰিবলৈ চৰকাৰে এই বিকল্প বিবেচনা কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অহা কেইদিনমানৰ ভিতৰতে প্রকাশ পাব পাৰে।

উৎসৱৰ বতৰত ইউপিআই বিনামূলীয়া থাকিব পাৰে

প্রস্তাৱিত ব্যৱস্থাটো কার্যকৰী হ'লে বৃহৎ ব্যৱসায়ীৰ ক্ষেত্রত ২,০০০ টকাৰ অধিক ইউপিআই লেনদেনত ০.৪ শতাংশ মার্চেণ্ট ডিস্কাউণ্ট ৰেট বা এমডিআৰ আৰোপৰ কথা আছিল। কিন্তু উৎসৱৰ বতৰত গ্রাহক আৰু ব্যৱসায়ীৰ ওপৰত অতিৰিক্ত চাপ নপৰিবলৈ এই নিয়মৰ কার্যকৰী তাৰিখ পিছুৱাই দিয়াৰ সম্ভাৱনা সৃষ্টি হৈছে।

গুৰুত্বপূর্ণ কথাটো হ'ল-এই মাচুল গ্রাহকৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ লোৱাৰ কথা নহয়। প্রস্তাৱিত এমডিআৰ মূলত ব্যৱসায়ীৰ ওপৰত আৰোপ হ'ব। অৱশ্যে ব্যৱসায়ীৰ খৰচ বৃদ্ধি পালে পৰোক্ষভাৱে সামগ্রী বা সেৱাৰ মূল্যত ইয়াৰ প্রভাৱ পৰাৰ আশংকা থাকিব পাৰে।

কোনে দিব লাগিব মাচুল ?

প্রস্তাৱিত নিয়ম অনুসৰি, মাহত ইউপিআইৰ জৰিয়তে ১ লাখ টকাৰ অধিক সংগ্রহ কৰা বৃহৎ ব্যৱসায়ীৰ ক্ষেত্রত ২,০০০ টকাৰ অধিক মূল্যৰ প্রতিটো লেনদেনত ০.৪ শতাংশ এমডিআৰ আৰোপ কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে। ইয়াৰ ওপৰত ১৮ শতাংশ জিএছটি প্রযোজ্য হোৱাৰ কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে।

আনহাতে, মাহত ইউপিআইৰ জৰিয়তে ১ লাখ টকালৈকে সংগ্রহ কৰা সৰু ব্যৱসায়ীক এই মাচুলৰ পৰা ৰেহাই দিয়াৰ প্রস্তাৱ আছে। অর্থাৎ সৰু দোকানী বা ক্ষুদ্র ব্যৱসায়ীৰ ওপৰত অতিৰিক্ত বোজা নপৰাৰ ব্যৱস্থা ৰখাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে।

একেটা ব্যৱসায়ীয়ে একেৰাহে তিনিমাহ ১ লাখ টকাৰ অধিক ইউপিআই সংগ্রহ কৰিলে তেওঁক বৃহৎ ব্যৱসায়ীৰ শ্রেণীত স্থানান্তৰ কৰাৰ ব্যৱস্থাও প্রস্তাৱিত নিয়মত আছে।

২,০০০ টকালৈ লেনদেনত মাচুল নাই

প্রস্তাৱিত কাঠামো অনুসৰি বৃহৎ ব্যৱসায়ীৰ ক্ষেত্রতো ২,০০০ টকা বা তাৰ তলৰ প্রতিটো ইউপিআই লেনদেনত মাচুল নলোৱাৰ কথা আছিল। ২,০০০ টকাৰ সীমা দিনটোৰ মুঠ লেনদেনৰ ওপৰত নহয়, প্রতিটো পৃথক লেনদেনৰ ভিত্তিত নির্ধাৰিত হ'ব।

৭৫,০০০ টকা বা তাতকৈ অধিক মূল্যৰ লেনদেনৰ ক্ষেত্রত সর্বাধিক ৩০০ টকা এমডিআৰ আৰু তাৰ ওপৰত জিএছটি আৰোপ কৰাৰ সীমা ৰখাৰ কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে।

কিছুমান খণ্ডত নির্দিষ্ট মাচুল

পেট্রল পাম্প, ৰে'ল সেৱা, বিল পৰিশোধ, টেলিকম, বীমা আৰু শিক্ষাৰ দৰে নির্দিষ্ট খণ্ডৰ ব্যৱসায়ীৰ ক্ষেত্রত ২,০০০ টকাৰ অধিক ইউপিআই লেনদেনৰ বাবে ০.৪ শতাংশৰ পৰিৱর্তে ৫ টকাৰ নির্দিষ্ট মাচুলৰ প্রস্তাৱ আছে।

এই ব্যৱস্থা কার্যকৰী হ'লে বৃহৎ লেনদেনৰ ক্ষেত্রতো মাচুলৰ পৰিমাণ সীমিত হৈ থাকিব।

ফিনটেক কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰত চাপ

ইউপিআই মাচুল পিছুৱাই দিয়াৰ খবৰ ওলোৱাৰ পিছত শ্বেয়াৰ বজাৰত তালিকাভুক্ত কেইবাটাও ফিনটেক কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰত চাপ দেখা যায়।

পেটিএমৰ শ্বেয়াৰ দিনটোৰ ব্যৱসায়ত এসময়ত প্রায় ১০ শতাংশলৈ হ্রাস পাইৰ, ৫৬১ টকাৰ নিম্নস্তৰ স্পর্শ কৰে। বজাৰ বন্ধ হোৱাৰ সময়ত অৱশ্যে কিছু উদ্ধাৰ হৈ ৫.৪২ শতাংশ হ্রাসেৰে ১,৬৪০ টকাত বন্ধ হয়।

ব্যৱসায়ী সংগঠনৰ আপত্তি

ইউপিআইত মার্চেণ্ট মাচুল আৰোপৰ প্রস্তাৱক লৈ ইতিমধ্যে ব্যৱসায়ী সংগঠনসমূহে আপত্তি প্রকাশ কৰিছে। তেওঁলোকৰ যুক্তি-খুচুৰা ব্যৱসায়ী আৰু বিতৰকসকলে বহু ক্ষেত্রত অতি কম লাভৰ হাৰত ব্যৱসায় কৰে। তেনে অৱস্থাত ডিজিটেল লেনদেনৰ ওপৰত অতিৰিক্ত মাচুল আৰোপ কৰিলে তেওঁলোকৰ খৰচ বৃদ্ধি পাব।

ব্যৱসায়ী সংগঠনসমূহৰ মতে, ইউপিআইয়ে নগদ ধনৰ ব্যৱহাৰ হ্রাস কৰাৰ লগতে লেনদেনক অধিক স্বচ্ছ কৰি তুলিছে। এনে ব্যৱস্থাক উৎসাহিত কৰাৰ পৰিৱর্তে মাচুল আৰোপ কৰিলে ডিজিটেল ভাৰতৰ লক্ষ্যত নেতিবাচক প্রভাৱ পৰিব পাৰে।

তেওঁলোকে চৰকাৰক সিদ্ধান্তটো পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে আৰু দাবী মানি নলৈলে আন্দোলন অধিক তীব্র কৰাৰ সতর্কবাণীও দিছে।

ডিজিটেল ভাৰতৰ সম্মুখত নতুন প্রশ্ন

ইউপিআই ভাৰতৰ ডিজিটেল অর্থনীতিৰ অন্যতম শক্তিশালী আধাৰ হৈ পৰিছে। চাহৰ দোকানৰ পৰা বৃহৎ বিপণীলৈকে, ৰে'ল টিকটৰ পৰা অনলাইন ক্রয়লৈকে-দৈনন্দিন জীৱনৰ প্রায় প্রতিটো স্তৰতে ইউপিআই এতিয়া সাধাৰণ লেনদেনৰ মাধ্যম।

সেয়েহে ইউপিআইৰ ওপৰত মাচুল আৰোপৰ যিকোনো সিদ্ধান্ত কেৱল পেমেণ্ট কোম্পানী বা ব্যৱসায়ীৰ বিষয় নহয়। ইয়াৰ সৈতে জড়িত আছে ডিজিটেল লেনদেনৰ ভৰিষ্যৎ, ক্ষুদ্র ব্যৱসায়ীৰ খৰচ আৰু সাধাৰণ গ্রাহকৰ ওপৰত সম্ভাব্য পৰোক্ষ প্রভাৱ।

যদি ১৫ অক্টোবৰৰ পৰিৱর্তে নতুন নিয়ম অহা বছৰৰ ১ জানুৱাৰীলৈ পিছুৱাই দিয়া হয়, তেন্তে অন্ততঃ উৎসৱৰ বতৰত ব্যৱসায়ী আৰু ডিজিটেল পেমেণ্ট খণ্ডই কিছু সকাহ লাভ কৰিব। কিন্তু মূল প্রশ্নটো তেতিয়াও থাকিব-দেশত ইউপিআইৰ দৰে ব্যাপকভাৱে ব্যৱহৃত ডিজিটেল লেনদেন ব্যৱস্থাৰ খৰচ কোনে বহন কৰিব ?

উত্তৰ-পূর্বাঞ্চলৰ জলপথে�ৰে ভূটানৰ বাবে বিশ্ববজাৰ মুকলিৰ সম্ভাৱনা: সর্বানন্দ

জন জন বিচাৰ
...নতুন দিল্লী



ভাৰতৰ আভ্যন্তৰীণ জলপথ আৰু সামুদ্রিক পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে ভূটানৰ দৰে স্থলবেষ্টিত দেশক বিশ্ববজাৰৰ সৈতে সংযোগ কৰাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে। কেন্দ্রীয় বন্দৰ, জাহাজ পৰিবহণ আৰু জলপথ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে বৃহস্পতিবাৰে নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত 'সাগৰমন্থন: দ্য গ্রেট অ'চৈনছ ডায়লগ'ত এই মন্তব্য কৰে।

সোণোৱালে কয় যে উত্তৰ-পূর্বাঞ্চলৰ ভৌগোলিক অৱস্থান ভূটানৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্রীয় বাণিজ্যৰ নতুন দুৱাৰ মুকলি কৰিব পাৰে। ভূটানৰ সাগৰীয় উপকূল নাথাকিলেও ভাৰতৰ জলপথৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰি দেশখনে বিশ্ববজাৰত প্রৱেশৰ সুযোগ লাভ কৰিব পাৰে।

তেওঁৰ মতে, ভূটানৰ পৰা প্রায় ১৫০ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত ব্রহ্মপুত্র নদী অৱস্থিত। ৰাষ্ট্রীয় জলপথ ব্যৱস্থাৰ অংশ হিচাপে ব্রহ্মপুত্রৰ জৰিয়তে বাংলাদেশ হৈ বংগোপসাগৰলৈ সামগ্রী পৰিবহণৰ সম্ভাৱনা আছে। ইয়াৰ ফলত ভূটানত উৎপাদিত সামগ্রী আন্তঃৰাষ্ট্রীয় বজাৰলৈ নিয়াৰ পথ সহজ হ'ব পাৰে। মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয় যে ভাৰতৰ সামুদ্রিক পৰিবহণ ব্যৱস্থাই কেৱল উপকূলীয় ৰাজ্যসমূহকেই নহয়, স্থলবেষ্টিত দেশসমূহকো বিশ্ব বাণিজ্যৰ সৈতে সংযোগ কৰাৰ ক্ষমতা ৰাখে।

বিদেশৰ পৰা ৪০ৰো অধিক জাহাজ নির্মাণৰ অর্ডাৰ

ভাৰতৰ জাহাজ নির্মাণ উদ্যোগৰ অগ্রগতিৰ কথা উল্লেখ কৰি সোণোৱালে কয় যে কোচিন শিপয়ার্ড লিমিটেডে জার্মানী, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্র আৰু নৰৱেকে ধৰি বিভিন্ন দেশৰ পৰা ৪০খনতকৈও অধিক জাহাজ নির্মাণৰ অর্ডাৰ লাভ কৰিছে। তেওঁৰ মতে, এই অর্ডাৰসমূহে ভাৰতীয় জাহাজ নির্মাণৰ মান, উৎপাদন ক্ষমতা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্রীয় বিশ্বাসযোগ্যতাৰ প্রতি বৃদ্ধি পোৱা আস্থাকে প্রতিফলিত কৰিছে।দেশত শক্তিশালী জাহাজ নির্মাণ ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাৰ বাবে চৰকাৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ কৰিছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে।

সেউজ ইন্ধন আৰু দক্ষতা বিকাশত গুৰুত্ব

সামুদ্রিক অর্থনীতিৰ ক্রমবর্ধমান সুযোগৰ সদ্ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যুৱপ্রজন্মক উপযুক্ত দক্ষতা আহৰণৰ আহ্বান জনায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগৰাকীয়ে। জাহাজ নির্মাণ, মেৰামতি, বন্দৰ পৰিচালনা আৰু সামগ্রী পৰিবহণৰ ক্ষেত্রত প্রশিক্ষিত কর্মীৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে বুলি তেওঁ কয়।লগতে হাইড্রজেন, এম'নিয়া, মিথানল আৰু ই-মিথানলৰ দৰে তুলনামূলকভাৱে পৰিৱেশ অনুকূল ইন্ধনৰ বিকাশৰ ওপৰতো তেওঁ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে।

বানপানীত ক্ষতিগ্রস্থ হোৱা ৰাইজৰ উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ আৰু পুনৰ সংস্থাপন , নাজিৰা সমজিলাৰ ঐতিহাসিক কীর্তিচিহ্ন সমূহৰ সংৰক্ষণ আৰু সৌন্দর্যবর্ধনৰ দাবী

টাইপাৰ অৱস্থান ধর্মঘট মুখ্যমন্ত্রীলৈ স্মাৰক পত্র



জন জন বিচাৰ
...✍ নাজিৰা

যোৱা ১৯ জুলাইত হোৱা প্রলয়ংকাৰী বানপানীত শিৰসাগৰ জিলাৰ ৩২৮খন গাঁৱৰ ৪ লাখ লোক, ৪২, ৫০০ তকৈও অধিক ঘৰ বানত প্লাবিত হৈ শোচনীয় পৰিস্থিতি সৃষ্টি হোৱাৰ পাছতো উপযুক্ত ক্ষতিপূৰকাটো বাদেই এতিয়ালৈকে অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰা ১৫, ০০০ টকাৰ এককালীন সাহায্যও সকলো পৰিয়ালে আজিকোপতি লাভ নকৰিলে। চৰকাৰে কৰা জৰীপৰ পৰাও বহুলোক বাদ পৰি যোৱা বুলি ৰাইজৰ মাজত অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। সেয়েহে নাজিৰা সম জিলা আয়ুক্তৰ কার্যালয়ৰ সম্মুখত টাইপাৰ কেন্দ্রীয় সমিতিৰ সভাপতি দিগন্ততামুলীৰ আহ্বান আৰু উপস্থিতিত, টাই আহোম মহিলা পৰিষদ, অসমৰ সহযোগত, টাই আহোম যুৱ পৰিষদ, অসম টাইপাৰ নাজিৰা মহকুমা সমিতিয়ে নাজিৰা সমজিলা আয়ুক্ত কার্যালয়ৰ সম্মুখত অৱস্থান ধর্মঘট কার্যসূচী ৰূপায়ন কৰে । কার্যসূচীৰ অন্তত

প্রলয়ংকাৰী বানপানীৰ মূল কাৰক হিচাপে অসমৰ ৰাইজে অবৈধ শিল আৰু কয়লা খনন বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে; সেয়েহে ইয়াৰ এক চি.বি.আই, তদন্ত ঘোষণা কৰিবৰ বাবে চৰকাৰক শীঘ্রে ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰা, বানত ক্ষতিগ্রস্ত লোকক শীঘ্রে উপযুক্ত ক্ষতিপূকাৰ ব্যৱস্থা কৰা , বানত ক্ষতিগ্রস্ত লোকৰ পুনৰ সংস্থাপন আৰু আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে শিৰসাগৰ জিলালৈ কেন্দ্রীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে কমেও ৩ হাজাৰ কোটি টকাৰ বিশেষ পেকেজ ঘোষণা কৰা , বানত ক্ষতিগ্রস্ত লোকৰ বাবে অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰা ১৫,০০০ টকাৰ এককালীন সাহায্য প্রদানত হোৱা বিসংগতি তদন্ত কৰি বাকী বৈ যোৱা লোকসকলক শীঘ্রে উক্ত ধনৰাশি প্রদান কৰা , নাজিৰা সমজিলাৰ বিভিন্ন প্রান্তত থকা ঐতিহাসিক কীর্তিচিহ্ন সমূহৰ উপযুক্ত সংৰক্ষণ আৰু সৌন্দর্যবর্ধনৰ ব্যৱস্থা কৰা আদিৰ দাবীত সমজিলা আয়ুক্তৰ জৰিয়তে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী আৰু সমজিলা আয়ুক্তক পৃথকে পৃথকে একোখনকৈ স্মাৰক পত্র প্রদান কৰে।

বজালীৰ শিক্ষক চাণক্য দাসলৈ ‘সমাজ সেৱক প্রেৰণা বঁটা’



জন জন বিচাৰ
...✍ পাঠশালা

সমাজ সেৱা, শিক্ষা আৰু সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রলৈ আগবঢ়োৱা উল্লেখযোগ্য অৱদানৰ স্বীকৃতি হিচাপে বজালীৰ শ্বহীদ কপিল কলিতা হাইস্কুলৰ সহকাৰী শিক্ষক তথা সমাজ সংগঠক চাণক্য দাসলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে ‘সমাজ সেৱক প্রেৰণা বঁটা’।

উত্তৰ-পূর্বাঞ্চল প্রেৰণা সমন্বয়ন চেবিটেবল ট্রাষ্টৰ উদ্যোগত প্রদান কৰা এই সন্মান যোৱা ৪ অক্টোবৰত গুৱাহাটীৰ পেঞ্চনাৰ ভৱনত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত চাণক্য দাসক প্রদান কৰা হয়।

ছাত্র জীৱনৰ পৰাই সমাজ সেৱাৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰা চাণক্য দাসে ১৯৮৫ চনৰ পৰাই সদৌ অসম ছাত্র সস্থাৰ সৈতে জড়িত হৈ বিভিন্ন সামাজিক কাম-কাজত সক্রিয়ভাৱে অংশগ্রহণ কৰি আহিছে। পৰৱর্তী সময়ত বাঘমাৰা অঞ্চল, বজালী আৰু অসম উন্নতি সভাৰ সৈতে জড়িত হৈ তেওঁ সামাজিক ক্ষেত্রত নেতৃত্ব বহন কৰে।

বজালীৰ এখন ভিতৰুৱা গাঁৱত জন্মগ্রহণ কৰা চাণক্য দাসে বাঘমাৰা অঞ্চলৰ বিভিন্ন সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক কার্যসূচীৰ সৈতে দীর্ঘদিন ধৰি ওতপ্রোতভাৱে জড়িত হৈ আছে। বিশেষকৈ বাঘমাৰা শ্রীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱৰ আয়োজন আৰু পৰিচালনাৰ ক্ষেত্রতো তেওঁৰ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে।

এই সপ্তাহৰ ৰাশিফল

৯ অক্টোবৰ ২০২৬ৰ পৰা ১৫ অক্টোবৰ ২০২৬ লৈ

মেষ : আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রত মনোনিবেশ থাকিব। ব্যাৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্রত শুভ ফল। আকস্মিক কোনো শুভ সংবাদ আহিব পাৰে।

বৃষ: চেষ্টাৰ সমাদৰ লাভ। প্রতিযগিতামূলক কার্য্যত সফলতা লাভ। ব্যাৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্রত শুভ।

মিথুন: অস্থিৰতা বৃদ্ধি হব পাৰে। আনন্দ ফূর্তিৰ মাজেৰে সপ্তাহটো পাৰ হব। আর্থিক ক্ষেত্রত সপ্তাহটো শুভ।

কর্কট: আর্থিক ক্ষেত্রত বাধাৰ সৃষ্টি হব পাৰে। মানসিক অস্থিৰতা বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীৰ বাৰে সপ্তাহটো শুভ।

সিংহ: শৰীৰ স্বাস্থঞ্জযৰ প্রতি সচেতন হব। ব্যয় বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আছে। ধর্মীয় ক্ষেত্রত মনোনিবেশ থাকিব।

কন্যা : আর্থিক ক্ষেত্রত সপ্তাহটো শুভ। আত্মীয় স্বজনৰ মাজত শুভ সময় কটোৱাৰ সুযোগ থাকিব। ভ্রমণৰ পৰা লাভ।

তুলা: আধ্যাত্মিক কার্য্যৰ পৰা মানসিক শান্তি। আকস্মিক কোনো শুভ সংবাদ আহিব পাৰে।

বৃশ্চিক: কর্মক্ষেত্রত সুনাম অর্জন। সামাজিক ব্যস্ততা বৃদ্ধি। ধর্মীয় কার্য্যৰ দ্বাৰা সমাদৰ লাভ।

ধনু : কর্মক্ষেত্রত আস্তিৰতা বৃদ্ধি। সামাজিক ক্ষেত্রত বাধাৰ সন্মুখীন হব পাৰে। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রৰ পৰা লাভ।

মকৰ: পিতৃৰ শৰীৰ স্বাস্থ্যৰ প্রতি সচেতন হব। কর্মক্ষেত্রত শুভ ফল দায়ক। সামাজিক কার্য্যৰ পৰা সুনাম অর্জন।

কুম্ভ : বার্তা বিনিময়ৰ ক্ষেত্রত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব। আকস্মিক ব্যয় বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আছে। কর্মক্ষেত্রত সপ্তাহটো শুভ।

মীন: পতি পত্নীৰ মাজত মতানক্য আহিব পাৰে। ব্যাৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্রত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব। ধর্মীয় কার্য্যত মনোনিবেশ থাকিব।

- হিতেন শর্মা শাস্ত্রী
অধ্যাপক, বিশ্ব জ্যোতিষ বিদ্যাপীঠ, অসম শাখা
যোগাযোগ : ৯৮৫৪০২৬৭৭৯

বানেধোৱা নাজিৰাৰ কালীবাৰী অঞ্চলত বিপদঘণ্টা দিখৌৰ ভগ্ন গার্ডৰালে বিপদ মাতিছে নাজিৰা নগৰলৈ

জন জন বিচাৰ
...✍ নয়নমণি ফুকন নাজিৰা



উজনি অসমৰ লগতে শিৰসাগৰ জিলাৰ নাজিৰা সমজিলাত ১৯ জুলাইত সংঘটিত হোৱা প্রলয়ংকাৰী বানে নাজিৰাবাসী ৰাইজলৈ বিপর্যয় লৈ অনাৰ পিছত সেই পৰিস্থিতিৰ লগত মোকাবিলা কৰি পুনৰ সুস্থিৰ অৱস্থালৈ আহিবলৈ যথেষ্ঠ প্রত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হবলগীয়া হৈছিল। নাজিৰা নগৰৰ ৭ নং ৰার্ডৰ বাসিন্দাসকলেও ভয়াৱহ বানত হোৱা সন্মুখীন হোৱা ক্ষয় ক্ষতিৰ বেদনা পৰিহাৰ কৰি পুনৰ নতুন জীৱন আৰম্ভ কৰিবলৈ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা চলাই অহাৰ সময়তে দিখৌ নদীয়ে এই অঞ্চলবাসীলৈ ভয়ংকৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা পৰিলক্ষিত হৈছে। শেহতীয়া ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতিৰ পিছত দিখৌ নদীৰ কাষৰীয়া ৭ নং ৰার্ডৰ কালীবাৰী অঞ্চলৰ নৰনির্মিত মথাউৰিৰ এটা অংশ বহি যোৱাৰ ওপৰিও দুটাকৈ স্থানত ফাট মেলিছে মথাউৰিৰ গার্ড ৰাল। সেই সুৰংগসদৃশ ফাঁকৰ বাবেই দিখৌ নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পালেই এতিয়া দুচিন্তাত দিন কটাবলগীয়া হৈছে স্থানীয় বাসিন্দাসকলে। ইফালে সেই স্থানতে আছে বিদ্যুৎ বিভাগৰ উচ্চ ক্ষমতাচালিত ১১,০০০ ভল্টেজৰ দুটা বিদ্যুতৰ খুটা। সেই উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুতৰ খুটা কিবা কাৰণত খহি পৰিলে এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পূর্ণ সম্ভাৱনা আছে। স্থানীয় লোকে বিদ্যুৎ বিভাগৰ লগতে জলসম্পদ বিভাগক বিষয়টো গুৰুত্বসহকাৰে লৈ ইয়াৰ এক স্থায়ী সমাধান কৰিবলৈ দাবী জনাইছে।

বানে বিধ্বস্ত কৰা শিক্ষানুষ্ঠানত ভাৰতৰ অস্ত্রোপচাৰ বিশেষজ্ঞৰ অসম ৰাজ্যিক অধ্যায় সংস্থাৰ সামগ্রী বিতৰণ

জন জন বিচাৰ
...✍ নয়নমণি ফুকন নাজিৰা



যোৱা ১৯ জুলাইত জলপ্রলয়ত বিধ্বস্ত হোৱা শিৱসাগৰ জিলাখনে ধৰি চৰাইদেউ, যোৰহাট জিলাৰ বিভিন্ন প্রান্তৰ জনগণৰ লগতে শিক্ষানুষ্ঠান সমূহতবহু সংস্থাই সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই আহিছে। শেহতীয়াকৈ বানে বিধ্বস্ত কৰা নাজিৰা সমজিলাৰ দহখন শিক্ষানুষ্ঠানত ভাৰতৰ অস্ত্রোপচাৰ বিশেষৰ অসম ৰাজ্যিক অধ্যায় সংস্থা এটা দলে বিদ্যালয় প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতৰণ কৰে ।সংস্থাটোৰ যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসক বিশাল ঠাকুৰ আৰু ডাক্তৰ নীলুপাল ভট্টাচার্যৰ নেতৃত্বত চিকিৎসকৰ এটা দলে নাজিৰা মেচাগড়ৰ যোগেন্দ্র নাথ বৰগোহাঁই প্রাথমিক বিদ্যালয়, সোন্দৰ পুখুৰীৰ ৩০৪ নং প্রাথমিক বিদ্যালয় , বাউলি মৈদাম প্রাথমিক বিদ্যালয় , নাজিৰাৰ আদর্শ বিদ্যা ভৱন, শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনকে নাজিৰা, গেলেকীৰ ১০ খনকৈ বানে বিধ্বস্ত কৰা বিদ্যালয়তে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় শৈক্ষিক সামগ্রী বিতৰণ কৰে। চিকিৎসকৰ দলটোৰ এনে পদক্ষেপক সংশ্লিষ্ট শিক্ষানুষ্ঠানৰ কর্তৃপক্ষ তথা শিক্ষক - কর্মচাৰী আৰু অভিভাৱক সকলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কৰিছে।

সেৱা সংকল্প অভিযান: নাজিৰাৰ অংগনৱাড়ী কর্মীসকলক সমজিলা আয়ুক্তৰ প্রশংসা পত্র প্রদান



নাজিৰা। ৰাজ্যজুৰি ৰূপায়ণ হৈ থকা সেৱা সংকল্প অভিযানৰ অংশ ৰূপে নাজিৰা সংহত শিশু উন্নয়ন প্রকল্পৰ অন্তর্গত অংগনৱাড়ী কেন্দ্র সমূহত অংগন মিলন সেৱা কার্য্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হয়।

এই কার্যসূচীৰ অধীনত নাজিৰাৰ সমজিলা আয়ুক্ত প্রতিভা মেশ্রামে কেতেকীবাৰী বনুৱা অংগনৱাড়ী কেন্দ্রত উপস্থিত হৈ অংগণ মেলাত অংশগ্রহণ কৰে। সমজিলা আয়ুক্ত প্রতিভা মেশ্রামে অংগনৱাড়ী কেন্দ্রটোৰ পৰিচালনাৰ বুজ লোৱাৰ লগতে অংগনৱাড়ী কর্মী আৰু শিশুসকলৰ সৈতে পোনপটীয়াভাৱে মত বিনিময় কৰে লগতে শিশুসকলক পুষ্টিকৰ আহাৰ বিতৰণ কৰে।

উল্লেখযোগ্য যে, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, শিশুৰ যত্ন আৰু পৰিপুষ্টিৰ ক্ষেত্রত নিষ্ঠাৰে আগবঢ়োৱা সেৱাৰ বাবে সমজিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে অংগনৱাড়ী কর্মীসকলক বিশেষভাৱে প্রশংসা কৰে আৰু তেওঁলোকক আনুষ্ঠানিক প্রশংসা পত্র প্রদান কৰে।

পৰিদর্শন কালত পোষণ বা পুষ্টিৰ ওপৰত এক গুৰুত্বপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়, য'ত অপৰিপুষ্টি ৰোধ আৰু শিশু সকলৰ সামগ্রিক বিকাশৰ ক্ষেত্রত অংগনৱাড়ী কেন্দ্র আৰু কর্মীসকলৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানত নাজিৰাৰ সংহত শিশু উন্নয়ন বিষয়া বর্ণিতা মিঠিহাৰিৰ লগতে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি, ৰাইজ আৰু বিভাগীয় বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে।

নাজিৰাৰ মেকীপুৰত বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হৈ এজনৰ মৃত্যু

নাজিৰা। নাজিৰা মেকীপুৰৰ পদুম পুখুৰী কৰৱস্থান চুকত বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হৈ বিদ্যুৎ বিভাগৰ এজন ব্যক্তিয়ে মৃত্যুক সাৱটি লয়। জানিব পৰা মতে মেকীপুৰৰ পদুম পুখুৰী কৰৱস্থান অঞ্চলত দুদিন ধৰি বিদ্যুৎ সেৱা ব্যাহত থকাত স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি শুকুৰবাৰে নিশা প্রায় ৯মান বজাত সেই অঞ্চলৰে বিদ্যুৎ বিভাগৰ ঠিকাভিত্তিক অস্থায়ী কর্মচাৰী মৃদুল ৰাজগড় নামৰ ব্যক্তিজনে এটা ট্রেক্সফমাৰত মেৰামতিৰ কৰি থকা অৱস্থাতেই বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হৈ মাটিত বাগৰি পৰে। ঘটনাৰ খবৰ পাই ব্যক্তিজনৰ ভাতৃয়ে ততাতৈয়াকৈ লিগিৰী পুখুৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ আনে যদিও চিকিৎসকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰে আৰু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্রেৰণ কৰে।

উল্লেখ্য যে চৰকাৰী কর্মচাৰী থকা সত্ত্বেও কিয় ঠিকাভিত্তিক অস্থায়ী কর্মচাৰীজনক অকলে মেৰামতি কৰিবলৈ কোনে পঠালে তাক লৈ স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত প্রশ্নৰ উদয় হৈছে। আকস্মিকভাৱে মৃদুল ৰাজগড়ে মৃত্যুক সাৱটি লক্ষ্মবলগীয়া হোৱাত অঞ্চলজুৰি তীব্র চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। মৃত্যুৰ সময়ত মৃদুল ৰাজগড়ে পত্নী, পুত্র আৰু এগৰাকী কন্যা এৰি থৈ যায়।

নাজিৰা মহাবিদ্যালয়ত 'সেৱা সংকল্প অভিযান'ৰ অধীনত সেৱা সেতু শিবিৰ

জন জন বিচাৰ
...✍ নয়নমণি ফুকন নাজিৰা



ৰাইজৰ কাষলৈ চৰকাৰী আঁচনি আৰু সেৱাসমূহ অধিক সহজে লৈ যোৱাৰ উদ্দেশ্যে 'সেৱা সংকল্প অভিযান'ৰ অংশ হিচাপে নাজিৰা উন্নয়ন খণ্ডৰ উদ্যোগত নাজিৰা মহাবিদ্যালয়ত দিনজোৰা কার্যসূচীৰে 'সেৱা সেতু শিবিৰ' অনুষ্ঠিত হয়। নাজিৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক ময়ূৰ বৰগোহাঁয়ে এই শিবিৰৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে। অনুষ্ঠানত শিৱসাগৰ জিলাৰ জিলা আয়ুক্ত মৃদুল যাদৱ, সমজিলা আয়ুক্ত প্রতিভা মেদ্রশ্রাম, নাজিৰাৰ সহকাৰী আয়ুক্তসকল, নাজিৰা খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া তথা বিভিন্ন চৰকাৰী বিভাগৰ মুৰব্বী বিষয়া আৰু কর্মচাৰীসকল উ পস্থিত থাকে । শিবিৰটোৰ জৰিয়তে একেটা স্থানতে ৰাইজক বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনি আৰু সেৱাৰ সৈতে সংযোগ স্থাপনৰ সুবিধা প্রদান কৰা হয়। ৰচটাতকৈও অধিক চৰকাৰী বিভাগে অংশগ্রহণ কৰা শিবিৰটোত আয়ুষ্মান ভাৰত— পি.এম.-জে.এ.ৰাই., পি.এম. গৰীৱ কল্যাণ অন্ন যোজনা, পি.এম.-কিষাণ, প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা, প্রধানমন্ত্রী জীৱন জ্যোতি বীমা যোজনা, ৰান নেশ্যন ৰান ৰেচন কার্ড, অৰুণোদয় দিব্যাংগসকলৰ বাবেৰে, ভূমি পট্টা, নামজাৰী, মাটি বিক্রীৰ অনুমতি, নতুন ৰেচন কার্ড, জন্ম-মৃত্যু প্রমাণ পত্র, নিযুত মইনা, নিযুত বাবু আদি বিভিন্ন আঁচনি আৰু সেৱাৰ অধীনত পঞ্জীয়ন, আবেদন গ্রহণ আৰু প্রয়োজনীয় সহায় আগবঢ়োৱা হয়।

শিবিৰটোত ৩,৫০০ৰো অধিক ৰাইজে অংশগ্রহণ কৰে। অংশগ্রহণকাৰীসকলে বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনি আৰু সেৱাৰ বাবে পঞ্জীয়ন কৰাৰ লগতে নিজ নিজ প্রয়োজন অনুসৰি উপলব্ধ সুবিধাসমূহ গ্রহণ কৰে।এনে পদক্ষেপৰ জৰিয়তে চৰকাৰী সেৱা লাভৰ প্রক্রিয়া অধিক সৰল আৰু সুবিধাজনক হোৱাৰ লগতে গ্রামাঞ্চলৰ ৰাইজে বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনি, সেৱা আৰু কল্যাণমূলক কার্যসূচীৰ বিষয়ে একে স্থানতে তথ্য লাভ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰে।

সম্পাদকীয়

কোচিং কাৰখানা আৰু উচ্চাকাংক্ষাৰ মূল্য

ভাৰতৰ প্রতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ প্রস্তুতিৰ নামত গঢ় লৈ উঠা প্রশিক্ষণ উদ্যোগ এতিয়া নতুনকৈ প্রশ্নৰ সন্মুখীন হৈছে। সীমিত আসন, অত্যধিক মাচুল আৰু অভিভাৱকৰ উচ্চাকাংক্ষাৰ বোজাই ছাত্র-ছাত্রীৰ জীৱনক ক্রমাৎ অধিক চাপপূর্ণ কৰি তুলিছে। গুৱাহাটীত ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রৰ দ্রুত সম্প্রসাৰণে এই সমস্যাক উত্তৰ-পূর্বাঞ্চলৰ বাবেও বিশেষভাৰে গুৰুত্বপূর্ণ কৰি তুলিছে।

প্রতি বছৰে লাখ লাখ শিক্ষার্থীয়ে চিকিৎসক অথবা অভিযন্তা হোৱাৰ সপোন পূৰণ কৰিবলৈ ঘৰ এৰি বিভিন্ন চহৰলৈ যায়। চিকিৎসা শিক্ষাৰ প্রৱেশ পৰীক্ষাত প্রায় ২৪ লাখ পৰীক্ষার্থীৰ বিপৰীতে চিকিৎসা স্নাতক পাঠ্যক্রমৰ আসন প্রায় ৮২ হাজাৰ। ফলত অধিকাংশ পৰীক্ষার্থীয়ে নিজৰ আকাংক্ষিত লক্ষ্যত উপনীত হ'ব নোৱাৰে। তথাপি বহু প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে সফলতাৰ আশ্বাস দি বিজ্ঞাপন প্রচাৰ কৰে। শীর্ষস্থান লাভ কৰা শিক্ষার্থীৰ ছবি আৰু সাফল্যৰ কাহিনীয়ে আন শিক্ষার্থীৰ ওপৰত অধিক মানসিক চাপ সৃষ্টি কৰে।

ৰাষ্ট্রীয় অপৰাধ অভিলেখ ব্যুৰ'ৰ তথ্য অনুসৰি, ২০২৩ চনত ভাৰতত ১৩,৮৯২ গৰাকী শিক্ষার্থীয়ে আত্মহত্যা কৰিছিল। এই ঘটনাসমূহৰ সকলোবোৰ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রৰ সৈতে জড়িত নহ'লেও পৰিসংখ্যাই শিক্ষার্থীৰ মানসিক সুস্থতাৰ প্রতি অধিক গুৰুত্ব দিয়াৰ প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট কৰে।

অসমত ২০২৫ চনত গৃহীত কোচিং প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ আইনখনে পদ্রঞ্জীয়ন, মাচুল আৰু সা-সুবিধাৰ স্বচ্ছতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। কিন্তু আইন প্রণয়ন কৰিলেই সমস্যাৰ সমাধান নহয়। নিয়মৰ কঠোৰ প্রয়োগ, উপযুক্ত মানসিক পৰামর্শ, অপমানজনক আচৰণ বন্ধ আৰু শিক্ষার্থীৰ সামর্থ্য অনুসৰি লক্ষ্য নির্ধাৰণ নিশ্চিত কৰিব লাগিব।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বন্ধ কৰাই এই সংকটৰ সমাধান নহয়। প্রয়োজন স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা আৰু অধিক চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপন। চৰকাৰ, শিক্ষানুষ্ঠান আৰু অভিভাৱকে একেলগে দায়িত্ব ল'ব লাগিব। কাৰণ শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য কেৱল পৰীক্ষাত উচ্চ স্থান লাভ নহয়; শিক্ষার্থীৰ জীৱন, মর্যাদা আৰু মানসিক সুস্থতা ৰক্ষা কৰাও সমানেই গুৰুত্বপূর্ণ।

বিকশিত ভাৰতৰ যাত্রাত থলুৱা ভাৰত যেন পিছ পৰি নাথাকে

জন জন বিচাৰ

...নৰেম মোহেন

২০৪৭ চনৰ ভিতৰত ভাৰতক এখন উন্নত ৰাষ্ট্র হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্য সাধাৰণতে অর্থনৈতিক বিকাশ, আন্তঃগাঁথনি, প্রযুক্তি, উৎপাদন আৰু বিশ্বজুৰি প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতাৰ ভাষাৰে আলোচনা কৰা হয়। কিন্তু এই লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ দিশে দেশখন আগবাঢ়ি যোৱাৰ সময়তে আন এটা প্রশ্নই সমান গুৰুত্ব লাভ কৰা উচিত-শতিকাজুৰি বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আৰু সম্প্রদায়ে সঞ্চয় কৰি অহা জ্ঞান, স্মৃতি আৰু প্রজ্ঞাৰ কোনখিনি ভাৰতে নিজৰ সৈতে আগুৱাই লৈ যাব?

এখন দেশে কেৱল কি কি নির্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল, তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি উন্নয়নৰ মূল্যায়ন কৰিব নোৱাৰি। নির্মাণৰ সমান্তৰালভাৱে নিজৰ ঐতিহ্যৰ কোনখিনি সংৰক্ষণ কৰাৰ বিবেচনা আৰু দূৰদৃষ্টি দেশখনে দেখুৱাব পাৰিছে, তাৰ ওপৰতো উন্নয়নৰ মূল্যায়ন নির্ভৰ কৰা উচিত।

মণিপুৰত এই প্রশ্নটোৱে এক বিশেষ তাৎপর্য লাভ কৰে। নীতি আয়োগৰ সদস্য ডক্টৰ জোৰাম অনিয়াই ইম্ফলস্থিত জৈৱসম্পদ আৰু বহনক্ষম উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানৰ শুভাই বি এছ ডিগ্না টাকিয়েল চৌহদত আয়োজিত এক বক্তৃতানুষ্ঠানত 'থলুৱা জ্ঞান ব্যৱস্থা আৰু বিকশিত ভাৰত' শীর্ষক বিষয়ত ভাষণ দিয়ে। জৈৱপ্রযুক্তি গৱেষণা আৰু উদ্ভাৱন পৰিষদৰ (বি আৰ আই) অন্তর্গত এই প্রতিষ্ঠানটোৰে আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানটোৰ মূল বক্তব্য আছিল স্পষ্ট আৰু গুৰুত্বপূর্ণ-ভাৰতীয় সমাজৰ এটা বৃহৎ অংশ আজিও গাঁও আৰু সম্প্রদায়ৰ সৈতে জড়িত থলুৱা জীৱনশৈলীৰ মাজেৰে নিজৰ পৰম্পৰাগত জ্ঞান ধৰি ৰাখিছে। প্রজন্মৰ পিছত প্রজন্মলৈ সঞ্চাৰিত এই জ্ঞান যাতে বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ সৈতে হেৰাই নাযায়, তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। একে সময়তে ইয়াক অতীতৰ মাজতে আবদ্ধ কৰি ৰখাৰ পৰিবর্তে সংৰক্ষণ, বৈজ্ঞানিক পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা আৰু ভৱিষ্যৎ প্রজন্মৰ প্রয়োজন অনুসৰি প্রয়োগৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব।

উত্তৰ-পূর্বাঞ্চলৰ ক্ষেত্রত এই আলোচনাৰ বিশেষ গুৰুত্ব আছে। এই অঞ্চলৰ জনগোষ্ঠীসমূহে প্রজন্মৰ পিছত প্রজন্ম ধৰি কৃষ্ণাঞ্চল, পাহাৰ, নদ-নদী, জলাশয় আৰু সমৃদ্ধ জৈৱবৈচিত্র্যৰ সৈতে সহাৱস্থান কৰি আহিছে। ঔষধি উদ্ভিদ, পৰম্পৰাগত কৃষি, ঋতুৰ পৰিৱর্তন, বীজ সংৰক্ষণ, খাদ্যাভ্যাস, বনসম্পদ আৰু প্রাকৃতিক সম্পদৰ বহনক্ষম ব্যৱহাৰ সম্পর্কে তেওঁলোকে আহৰণ কৰা জ্ঞান সদায় গৱেষণাগাৰ বা শৈক্ষিক গৱেষণা-পত্রৰ পৰা অহা নাছিল। ইয়াৰ বহু অংশই আছিল প্রকৃতিৰ সৈতে দীর্ঘদিনীয়া সহাৱস্থান, পর্যবেক্ষণ আৰু বাস্তৱ অভিজ্ঞতাৰ ফল।

ইয়াৰ অর্থ এইটো নহয় যে প্রতিটো পৰম্পৰাগত বিশ্বাসক বিনা পৰীক্ষাই বৈজ্ঞানিক সত্য বুলি মানি ল'ব লাগিব। একেদৰে, কোনো জ্ঞান আধুনিক প্রতিষ্ঠানৰ পৰিৱর্তে মৌখিক পৰম্পৰাৰ মাজেৰে প্রজন্মান্তৰলৈ সঞ্চাৰিত হৈছে বুলিয়েই তাক নস্যাৎ কৰাটোও বুদ্ধিমত্তাৰ পৰিচয় নহয়। অধিক যুক্তিসংগত পথটো হ'ল-সম্প্রদায়সমূহৰ জ্ঞান লিপিবদ্ধ কৰা, বৈজ্ঞানিক পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে তাৰ সত্যতা নিৰূপণ কৰা আৰু পৰম্পৰাগত অভিজ্ঞতা তথা আধুনিক গৱেষণাৰ মাজত এক সহযোগিতামূলক ক্ষেত্র সৃষ্টি কৰা।

এই ক্ষেত্রত আই বি এছ ডিৰ দৰে প্রতিষ্ঠানে অধিক গুৰুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে। থলুৱা জ্ঞান আৰু আধুনিক বিজ্ঞানক উন্নয়নৰ দুটা বিপৰীত মেৰু হিচাপে চোৱাৰ প্রয়োজন নাই। পৰম্পৰাগত জ্ঞানে প্রজন্মজুৰি সঞ্চিত পর্যবেক্ষণ আৰু অভিজ্ঞতাৰ ভঁৰাল আগবঢ়াব পাৰে; আনহাতে আধুনিক বিজ্ঞানে সেই জ্ঞান পৰীক্ষা, সত্যাপন, পৰিশোধন অথবা প্রয়োজন অনুসৰি নাকচ কৰাৰ পদ্ধতি প্রদান কৰে।

এই সহযোগিতা যদি পাৰস্পৰিক সম্মানৰ ভিত্তিত গঢ়ি তোলা হয়, তেন্তে ইয়াৰ সুফল কেৱল ঐতিহ্য সংৰক্ষণতে সীমাবদ্ধ নাথাকিব। কৃষি, জৈৱবৈচিত্র্য সংৰক্ষণ, স্বাস্থ্যসেৱা, জলবায়ু পৰিৱর্তনৰ সৈতে মোকাবিলা আৰু বহনক্ষম জীৱিকাৰ ক্ষেত্রতো ইয়াৰ ইতিবাচক প্রভাৱ পৰিব পাৰে। অৱশ্যে এই সমগ্র প্রক্রিয়াত যিসকল সম্প্রদায়ৰ পৰা জ্ঞান আহৰণ কৰা হয়, তেওঁলোকক কেৱল গৱেষণাৰ বিষয়বস্তু হিচাপে গণ্য কৰিলে নহ'ব। তেওঁলোকক সক্রিয় অংশীদাৰ আৰু লাভৰ ন্যায্য অংশীদাৰ হিচাপে স্বীকৃতি দিব লাগিব।

ডঃ অনিয়াৰ মণিপুৰ ভ্রমণ কেৱল শৈক্ষিক আলোচনাতে সীমাবদ্ধ নাছিল। ভ্রমণকালত তেওঁ ৰাজ্যপাল অজয় কুমাৰ ভাল্লা আৰু মুখ্যমন্ত্রী যুমনাম খেমচান্দ সিঙক সাক্ষাৎ কৰাৰ লগতে ৰাজ্য প্রশাসনৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰে। মুখ্যমন্ত্রীৰ সৈতে হোৱা আলোচনাত মণিপুৰৰ উন্নয়নৰ অগ্রাধিকাৰ আৰু নীতি আয়োগৰ অধীনত প্রস্তাৱিত ৰাজ্যিক ৰূপান্তৰ প্রতিষ্ঠানৰ বিষয়েও আলোচনা হয়। ইয়াৰ ফলত থলুৱা জ্ঞান, ঐতিহ্য আৰু পৰিৱেশৰ সৈতে জড়িত আলোচনাৰ লগতে ভ্রমণটোৱে এক নীতিগত মাত্রাও লাভ কৰে। আনহাতে, চৰকাৰী কার্যালয়ৰ পৰিসৰৰ বাহিৰতো বিভিন্ন লোকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি তেওঁ মণিপুৰৰ সমাজ জীৱনৰ বিভিন্ন দিশৰ সৈতে পৰিচিত হোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰে।

ইতিহাসৰ সৈতে মণিপুৰৰ সংযোগ

ডঃ অনিয়াৰ মৈৰাং ভ্রমণে তেওঁৰ এই যাত্রাত এক ঐতিহাসিক মাত্রা সংযোজন কৰে। তেওঁ আৰু তেওঁৰ দলে ঐতিহাসিক আজাদ হিন্দ ফৌজৰ মুখ্য কার্যালয় আৰু আই এন এ সংগ্রহালয় পৰিদর্শন কৰে। ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্রামৰ ইতিহাসৰ সৈতে মণিপুৰৰ গভীৰ সম্পর্কৰ সাক্ষ্য বহন কৰে এই স্থানসমূহে। ১৯৪৪ চনৰ এপ্রিল মাহত ভাৰতীয় ভূখণ্ডত আজাদ হিন্দ ফৌজৰ পতাকা উত্তোলন কৰা হৈছিল মৈৰাঙত। সেইবাবেই ভাৰতৰ ইতিহাসত এই স্থানৰ এক বিশেষ স্থান আছে।

দেশৰ অন্যতম গুৰুত্বপূর্ণ নীতি-নির্ধাৰণকাৰী প্রতিষ্ঠানৰ এগৰাকী সদস্যৰ বাবে এই ঐতিহাসিক স্থানত উপস্থিত হোৱাটো এটা স্মৰণীয় অভিজ্ঞতা হোৱাৰ লগতে এক গুৰুত্বপূর্ণ উপলব্ধিৰো মুহূর্ত। ভাৰতৰ ইতিহাসৰ বহু নির্ণায়ক অধ্যায় সেইবোৰ অঞ্চলত ৰচিত হৈছিল, যিবোৰ ৰাজনৈতিক কেন্দ্রৰ পৰা বহু দূৰত অৱস্থিত আৰু যিবোৰৰ অৱদান ৰাষ্ট্রীয় আলোচনাত প্রায়ে পর্যাপ্তভাৱে প্রতিফলিত নহয়।

মৈৰাঙৰ পৰা যাত্রাই ইতিহাসৰ পৰা প্রকৃতিৰ দিশে গতি কৰে। দলটোৱে লোকটক হ্রদৰ মাজেৰে যাত্রা কৰাৰ পাছত কেইবুল লামজাও ৰাষ্ট্রীয় উদ্যান পৰিদর্শন কৰে। ভাসমান ফুমদি বা উদ্ভিদজাত জৈৱপিণ্ডৰ বাবে বিখ্যাত এই অঞ্চল বিপন্ন প্রজাতিৰ চাংগাই হৰিণৰ প্রাকৃতিক বাসস্থান। ডক্টৰ অনিয়াৰ সৈতে এই অংশৰ ভ্রমণত উপস্থিত থকা মণিপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ অধ্যাপক তথা বিভাগীয় মুৰব্বী অধ্যাপিকা খেলেনা গুৰুমায়ুমে ভাসমান ফুমদিৰ মাজত পাঁচটা চাংগাই হৰিণ দেখাৰ আনন্দৰ কথা স্মৰণ কৰে।

এই যাত্রাই ব্যক্তিগত স্মৃতিৰো দুৱাৰ মুকলি কৰে। লোকটকৰ অনন্য প্রাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজেৰে যাত্রা কৰাৰ সময়ত ডক্টৰ অনিয়া আৰু অধ্যাপিকা গুৰুমায়ুমে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰা দিনবোৰৰ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰে। এই অভিজ্ঞতাই পুনৰ প্রমাণ কৰে যে ইতিহাস, সমাজ আৰু প্রকৃতিৰ মাজৰ সম্পর্ক কিমান গভীৰ আৰু অবিচ্ছেদ্য। ইম্ফলৰ শ্রীশ্রী গোবিন্দজী মন্দিৰ পৰিদর্শনে এই ভ্রমণত আন এক মাত্রা সংযোজন কৰে। মন্দিৰটো কেৱল ইম্ফলৰ এটা উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় স্থানেই নহয়; ই এক জীৱন্ত ঐতিহ্যৰ অংশ, য'ত ধর্মীয় বিশ্বাস, ইতিহাস, স্থাপত্য আৰু সামূহিক স্মৃতিৰ সমন্বয় ঘটিছে।

থলুৱা জ্ঞান সংৰক্ষণৰ গুৰুত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়াৰ সময়তে এই ঐতিহ্যবাহী স্থানসমূহ পৰিদর্শন কৰাটোও তাৎপর্যপূর্ণ। কাৰণ, সংৰক্ষণৰ অর্থ কেৱল গৱেষণাগাৰ, পুথিভঁৰাল বা সংগ্রহালয়ত তথ্য সাঁচি ৰখা নহয়। ধর্মীয় স্থান, ঐতিহাসিক ক্ষেত্র, সাংস্কৃতিক আচাৰ-অনুষ্ঠান আৰু তাৰ সৈতে জড়িত সামূহিক স্মৃতিৰ মাজেৰেও এখন সমাজে নিজৰ ঐতিহ্য বহন কৰে। এইদৰে আই বি এছ ডিৰ বক্তৃতানুষ্ঠান, নীতিগত আলোচনা, মৈৰাঙৰ ইতিহাস, লোকটক হ্রদ, কেইবুল লামজাও ৰাষ্ট্রীয় উদ্যান আৰু গোবিন্দজী মন্দিৰ-এই সকলোবোৰ কেৱল এটা ভ্রমণসূচীৰ পৃথক পৃথক গন্তব্যস্থান নহয়। এইবোৰে একেলগে বিকশিত ভাৰতৰ সম্মুখত থকা বৃহত্তৰ প্রশ্নটোৰ প্রতিফলন ঘটায়-আধুনিকতাৰ দিশে দৃঢ়তাৰে আগবাঢ়ি যোৱাৰ সময়ত এখন দেশে নিজৰ অঞ্চলসমূহৰ স্বকীয় পৰিচয় গঢ়ি তোলা জ্ঞান, ইতিহাস, বিশ্বাস, জৈৱবৈচিত্র্যঞ্জয় আৰু সাংস্কৃতিক স্মৃতিক কেনেকৈ অক্ষুণ্ণ ৰাখিব পাৰে?

বাংলাদেশত মৌলবাদী শক্তিৰ উত্থানক লৈ তছলিমা নাছৰিনৰ উদ্বেগ

জন জন বিচাৰ
...নতুন দিল্লী

বাংলাদেশৰ সাম্প্ৰতিক ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি আৰু দেশখনত মৌলবাদী তথা চৰমপন্থী শক্তিৰ প্ৰভাৰ বৃদ্ধিক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰবাসী বাংলাদেশী লেখিকা তছলিমা নাছৰিনে। বুধবাৰে কলকাতাৰ নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈ সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত নাছৰিনে অভিযোগ কৰে যে বাংলাদেশত চৰমপন্থী শক্তিসমূহক প্ৰশ্ৰয় দিয়াৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে।

তেওঁ স্পষ্টকৈ কয় যে বাংলাদেশক এখন 'সুস্থ আৰু সভ্য' দেশ হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ হ'লে মৌলবাদী আৰু চৰমপন্থী শক্তিৰ বিৰুদ্ধে দৃঢ়ভাৱে থিয় দিব লাগিব। নাছৰিনৰ মতে, কোনো দেশৰ সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক পৰিৱেশত ধৰ্মীয় মৌলবাদে অধিক প্ৰভাৰ বিস্তাৰ কৰিলে গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধ, মতপ্ৰকাশৰ স্বাধীনতা আৰু নাৰী অধিকাৰো প্ৰশ্নৰ সম্মুখীন হয়।



ভাৰত-বাংলাদেশৰ সম্পৰ্কক লৈ আশাবাদী

ভাৰত-বাংলাদেশৰ দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ প্ৰসংগত অৱশ্যে নাছৰিনে আশাবাদ প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ আশা কৰে যে দুয়োখন দেশৰ মাজৰ সম্পৰ্ক বন্ধুত্বপূৰ্ণ আৰু ইতিবাচক হৈ থাকিব। বাংলাদেশ চৰকাৰে চৰমপন্থী শক্তিৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলিও তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে।

বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তাৰিক ৰহমানৰ সম্ভাব্য ভাৰত ভ্ৰমণ আৰু তাৰ ফলত দুয়োখন দেশৰ সম্পৰ্কত কেনে প্ৰভাৰ পৰিব পাৰে বুলি সোধাত নাছৰিনে পৰিস্থিতি এতিয়াও অনিশ্চিত বুলি মন্তব্য কৰে। তেওঁৰ মতে, বাংলাদেশত জামাত-এ-ইছলামিৰ দৰে শক্তিক প্ৰশ্ৰয় দিয়াৰ অভিযোগ আৰু চৰমপন্থীসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ আশংকাই দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ ভৰিষ্যৎ সম্পৰ্কে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে।

কলকাতালৈ ঘূৰি আহি সুখী নাছৰিন

জুলাই মাহৰ পিছত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে কলকাতাত উপস্থিত হোৱা নাছৰিনে চহৰখনলৈ উভতি আহি সুখী হোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰে। অৱশ্যে এইবাৰ দুৰ্গাপূজাৰ সময়ছোৱাত কলকাতাত দীঘলীয়া সময় থাকিব নোৱাৰিব বুলিও তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে। কলকাতাৰ দুৰ্গাপূজাৰ প্ৰতি তেওঁৰ বিশেষ আকৰ্ষণ আছে বুলি উল্লেখ কৰি নাছৰিনে পূজাৰ শিল্পসজ্জাক এটা কলা প্ৰদৰ্শনীৰ সৈতে তুলনা কৰে।

কলকাতাত তেওঁৰ কেইবাটাও সাহিত্যিক আৰু সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীও অনুষ্ঠিত হব। 'শিকল ভাঙৰ গল্প' শীৰ্ষক অনুষ্ঠানত তেওঁ নিজৰ কবিতা পাঠ কৰিব। অনুষ্ঠানটো নাৰী, প্ৰেম, আকাংক্ষা, দুখ, প্ৰতিবাদ আৰু নিজৰ অধিকাৰ অনুসৰি জীৱন যাপনৰ অধিকাৰক কেন্দ্ৰ কৰি অনুষ্ঠিত হ'ব। ১১ অক্টোবৰত ছল্ট লেকত 'সাহিত্যত শালীনতা আৰু অশ্লীলতাৰ সীমা' শীৰ্ষক বিষয়ত তেওঁ বক্তব্য আগবঢ়াব। একেটা অনুষ্ঠানতে শিশুসকলৰ বাবে লিখা তেওঁৰ ইংৰাজী গ্ৰন্থ 'Jasmine' মুকলি কৰাৰ কথাও আছে।

মহালয়াত অংশ লোৱাৰ ইচ্ছা

নাছৰিনে ১০ অক্টোবৰত ইডেন গার্ডেনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া মহালয়া অনুষ্ঠানত অংশ লোৱাৰ চেষ্টা কৰিব বুলিও কয়। সময় পালে কোঁলাঘাটলৈ গৈ ইলিশ মাছৰ সোৱাদ লোৱাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে বিদ্যাসাগৰৰ জন্মস্থান বীৰসিংহ আৰু শৰৎচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়ৰ হাওড়াস্থিত বাসভৱনলৈ যোৱাৰো ইচ্ছা ব্যক্ত কৰে। প্ৰায় ১৯ বছৰৰ পিছত চলিত বছৰৰ ৩১ জুলাইত কলকাতালৈ উভতি আহিছিল তছলিমা নাছৰিন। তেওঁৰ কলকাতালৈ এই পুনৰাগমন কেৱল সাহিত্যিক উপস্থিতি নহয়; বাংলাদেশৰ ৰাজনীতি, মৌলবাদ আৰু ভাৰত-বাংলাদেশ সম্পৰ্কক লৈ তেওঁৰ বক্তব্যই পুনৰ আঞ্চলিক ৰাজনীতিত চৰ্চা লাভ কৰিছে।

খাৰুৱা তেলৰ দাম ৰঙ্গু ডলাৰ অতিক্ৰম, মধ্যকালীন নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ইৰানত আক্ৰমণ নকৰাৰ ঘোষণা ট্ৰাম্পৰ

জন জন বিচাৰ
...নতুন দিল্লী

আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পে ৩ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া মধ্যকালীন নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ইৰানৰ ওপৰত নতুনকৈ সামৰিক আক্ৰমণ নচলোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। বৃহস্পতিবাৰে তেওঁ কয় যে ইৰানৰ সৈতে ইতিবাচক আলোচনা অব্যাহত আছে। তেওঁৰ এই মন্তব্যৰ পিছতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত খাৰুৱা তেলৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ গতি কিছু হ্ৰাস পায়। অৱশ্যে দিনটোৰ ভিতৰত খাৰুৱা তেলৰ দাম পাঁচ শতাংশতকৈ অধিক বৃদ্ধি পাই প্ৰতি বেৰেলত ১০৩ ডলাৰ অতিক্ৰম কৰিছিল। ব্ৰেণ্ট খাৰুৱা তেলৰ মূল্য ১০৩.৭৩ ডলাৰ পৰ্যন্ত হৈছিল। ট্ৰাম্পে নিজৰ 'ট্ৰুথ ছ'চিয়েল' মঞ্চত প্ৰকাশ কৰা বক্তব্যত কয় যে ইৰানৰ বন্দৰসমূহৰ ওপৰত আমেৰিকাৰ অৱৰোধ অব্যাহত আছে আৰু হৰমুজ



প্ৰণালীৰে তেল পৰিবহণ চলি আছে। যুদ্ধৰ অৱসান আৰু হৰমুজ প্ৰণালীত জাহাজৰ চলাচল স্বাভাৱিক কৰাৰ উদ্দেশ্যে দুয়োখন দেশৰ মাজত পৰোক্ষ আলোচনা চলি আছে। ইফালে, ইৰানৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী আব্বাছ আৰাঘচিয়ে জনায় যে সাত দিনৰ ভিতৰত হৰমুজ প্ৰণালী মুকলি কৰাৰ প্ৰস্তাৱ সন্দৰ্ভত আমেৰিকাৰ উত্তৰ পৰ্যালোচনা কৰি থকা হৈছে। মধ্যস্থতাকাৰীৰ জৰিয়তে দুয়োপক্ষৰ মাজত বাৰ্তা বিনিময় অব্যাহত আছে। চৰ্তসমূহ পূৰণ হ'লে এসপ্তাহৰ ভিতৰত স্বাভাৱিক সামুদ্ৰিক যাতায়াত পুনৰ আৰম্ভ হ'ব পাৰে।

যুদ্ধত সামৰিক বিমান আৰু ড্ৰনৰ ক্ষতি

আমেৰিকাৰ কংগ্ৰেছনেল বিছার্চ ছার্ভিচৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ইৰানৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা যুদ্ধত আমেৰিকাৰ কমেও ৮১খন সামৰিক বিমান আৰু চালকবিহীন আকাশীযান ক্ষতিগ্ৰস্ত অথবা ধ্বংস হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত ৪৫খন এমকিউ-৯ ৰিপাৰ ড্ৰন আৰু ৰচখন এফ-ৰপ্তই ষ্ট্ৰাইক ঈগল যুদ্ধবিমান আছে। এখন এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান আৰু সাতখন কে চি-১৩৫ টেংকাৰ বিমানৰো ক্ষতি হোৱা বুলি প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে।

হৰমুজত বিপদসংকুল যাত্ৰাৰ বাবে অধিক পাৰিশ্ৰমিক

আল জাজিৰাৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, হৰমুজ প্ৰণালীৰে বিপদৰ মাজত তেল পৰিবহণ কৰা জাহাজৰ অধিনায়ক সকলক অধিক পাৰিশ্ৰমিক আৰু বিশেষ পুৰস্কাৰ দিয়া হৈছে। কিছুমান অধিনায়কে মাহে এক লাখ ডলাৰ পৰ্যন্ত দৰমহা আৰু প্ৰতিটো যাত্ৰাৰ বাবে অতিৰিক্ত ৫০ হাজাৰ ডলাৰ লাভ কৰিছে। সাধাৰণ অৱস্থাত তেওঁলোকৰ মাহিলি দৰমহা প্ৰায় ১৫ হাজাৰ ডলাৰ।

হৰমুজ প্ৰণালী সম্পূৰ্ণ বন্ধ নহয় বুলি আমেৰিকাৰ দাবী

আমেৰিকাৰ কেন্দ্ৰীয় সামৰিক কমাণ্ডে হৰমুজ প্ৰণালী সম্পূৰ্ণ বন্ধ বুলি ইৰানে কৰা দাবী নাকচ কৰিছে। কমাণ্ডৰ মতে, এই জলপথেৰে বাণিজ্যিক জাহাজ আৰু শক্তি সম্পদৰ পৰিবহণ অব্যাহত আছে। আনহাতে, ইৰানৰ বিপ্লবী ৰক্ষী বাহিনীৰ উপদেষ্টা মহম্মদৰেজা নাকদীয়ে হৰমুজ প্ৰণালীৰ ওপৰত ইৰানৰ সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণ থকা বুলি দাবী কৰিছিল। ট্ৰাম্পৰ আক্ৰমণ নকৰাৰ ঘোষণাই কূটনৈতিক আলোচনাৰ বাবে কিছু সুযোগ সৃষ্টি কৰিলেও হৰমুজ প্ৰণালীৰ নিৰাপত্তা আৰু খাৰুৱা তেলৰ মূল্যৰ অনিদ্ৰশ্চয়তা এতিয়াও অব্যাহত আছে।

GAURANSHI
INDUSTRIES

Gunika™

Purity in Every Drop, Nature in Every Product.

100% NATURAL



TEA

NAME	MAKHANA (FOX NUT SUPERFOOD)	ASSAM CTC TEA	ASSAM CTC TEA
SIZE	200gm	250gm	100gm

HONEY



NAME	MORINGA HONEY	TULSI HONEY
SIZE	200gm	200gm



NAME	MUSTARD HONEY	LITCHI HONEY	WILD FOREST HONEY
SIZE	200gm	200gm	200gm

RAW & UNPROCESSED | PURE & NATURAL | DIRECTLY FROM OUR FARMS | TRUSTED BY THOUSANDS

3rd Floor, IIT Road,
Jayguru, Amingaon,
Kamrup, Assam - 781031, India

Contact :
+91-88224 20619

E-Mail :
gauranshiind@gmail.com
www.gauranshiindustries.com



VOICE OF ALL, FOR ALL

WEEKLY

JAN JAN VICHAR

Guwahati, Friday, 9 October 2026



Why Washington's New Immigration Offensive Matters to Indian IT

Jan Jan Vichar
...✍New Delhi



For decades, the relationship between India's technology industry and the United States has been built around one powerful equation: American companies need skilled professionals, and Indian technology firms have supplied a large part of that talent. That equation is now under increasing pressure. The Trump administration's latest immigration measures have placed major technology companies under greater scrutiny over their use of foreign workers and employment-based immigration programmes. The development has triggered concern across India's IT industry, particularly among professionals who depend on US employment and those hoping to eventually obtain permanent residency. At the centre of the controversy is the H-1B visa, but another programme—PERM, or Permanent Labor Certification—is equally important for understanding what is happening.

First, H-1B and PERM are not the same thing

The distinction matters. The H-1B programme allows US employers to employ foreign workers in specialised occupations for a temporary period, subject to federal rules and annual limitations. PERM, on the other hand, is a Department of Labor process generally used when an employer wants to sponsor a foreign worker for permanent employment and eventually an employment-based green card. Under PERM, employers generally have to demonstrate that there are not sufficient qualified, willing and available US workers for the particular position and that employing the foreign worker will not adversely affect the wages and working conditions of similarly employed American workers. In other words, H-1B can be a pathway into the US workforce; PERM can become an important step toward permanent residency. That is why restrictions on PERM access can have consequences well beyond a single visa application.

Why Indian IT companies are watching closely

Major Indian-origin technology and IT-services companies have built extensive operations in the United States. Companies such as TCS, Infosys, Wipro, HCLTech, Cognizant and others employ large numbers of professionals across software development, consulting, cloud computing, cybersecurity, engineering and business services. For these companies, immigration policy is not simply an administrative matter. It can affect where employees are located, how projects are staffed, how long workers can remain in the United States and whether experienced foreign professionals can eventually obtain permanent residency. A tougher immigration environment can therefore increase costs and make workforce planning considerably more complicated.

Washington's argument Protect American workers

The Trump administration's position is built around a straightforward political argument: American immigration programmes should not be used to replace US workers, suppress wages or give employers access to cheaper foreign labour. Vice President JD Vance has sharply criticised major technology companies over their use of foreign-worker programmes. In the case of Microsoft, the administration has alleged that the company laid off thousands of American employees while also making extensive use of H-1B workers and green-card processes. The administration argues that such practices undermine the original purpose of skilled-worker immigration. That argument has considerable political resonance in an America where concerns about employment, wages and economic insecurity have become central to national politics. But the issue is more complicated than the slogan of "American jobs versus foreign workers."

The technology industry's counterargument

American technology companies have long argued that the US economy does not always produce enough workers with highly specialised skills. Artificial intelligence, semiconductor technology, cybersecurity, advanced software engineering, data science and other rapidly expanding fields require expertise that companies say can be difficult to find in sufficient numbers domestically. Indian professionals have been particularly important in this ecosystem. Many arrive in the United States after completing advanced degrees or through employment with multinational technology companies. Some eventually become managers, entrepreneurs and technology executives. The debate therefore involves two competing objectives: protecting American workers while ensuring that American companies can access the specialised talent they need. Finding the balance is proving increasingly difficult.

What PERM restrictions could mean

If a company loses access to the PERM process, the immediate impact is not that all of its H-1B employees suddenly lose their visas. That distinction is critical. A PERM-related restriction primarily affects the employer's ability to pursue certain employment-based permanent-residency cases.

For an Indian professional who has spent years working legally in America, however, that can be a major issue. Indian nationals face some of the longest waits in employment-based green-card categories because of per-country limits and the enormous number of applicants from India. A disruption in the green-card process can therefore prolong uncertainty for workers who may already have spent many years in the United States.

The hidden problem employee retention

This is where the issue becomes an economic problem for Indian IT companies. Highly experienced employees are expensive to replace. If immigration uncertainty makes it difficult for professionals to remain in the United States permanently, companies may have to move employees between countries, restructure teams or rely more heavily on locally hired American workers. That may increase operating costs. For workers, meanwhile, uncertainty can influence major life decisions involving housing, children's education, family relocation and long-term financial planning. The immigration debate therefore reaches far beyond a visa stamp.

America's larger immigration shift

The latest measures are part of a much broader change in Washington's approach to skilled immigration. The administration has indicated that immigration programmes should be subjected to greater scrutiny and should primarily serve what it considers the interests of American workers. International students are also facing greater uncertainty. The US administration has proposed a major fee for certain participants in the Optional Practical Training (OPT) system, which allows eligible international students to work in jobs related to their academic fields after or during their studies under specified rules.

Himanta Defends Action Against CJP Protesters, Cites Lack of Permission

Jan Jan Vichar
...✍Guwahati



The Assam government's decision to stop a protest by the Cockroach Janta Party (CJP) outside Janata Bhawan has raised questions about the regulation of political demonstrations and the right to peaceful dissent. Chief Minister Himanta Biswa Sarma has defended the police action, stating that the organisers had not obtained permission to stage the protest at the location where party workers assembled.

According to Sarma, the government had initially granted permission for the CJP to hold its demonstration at a designated venue in Chachal. The party subsequently requested permission for a second venue, which was also approved.

However, the Chief Minister said the protesters later gathered at the residence of Dudul Choudhury, opposite Janata Bhawan, without obtaining the necessary authorisation for that location.

First of all, I gave permission to the government-designated place in Chachal. Then they asked for a second venue. I gave permission for the second venue as well," Sarma said, explaining the government's position. He added that the administration intervened to prevent a disturbance outside the government headquarters. Police arrested CJP workers who assembled at the unauthorised location, according to the report.

Protest, Permission and Democratic Rights

The incident brings into focus the delicate balance between maintaining public order and protecting the democratic right to protest. While authorities can impose reasonable restrictions to ensure security and prevent disruption, such powers must be exercised transparently and consistently. The government maintains that the action was prompted by the absence of permission for the specific location, rather than a blanket denial of the party's right to demonstrate. However, a complete assessment would require the protesters' response and further details about the police action. In a democracy, peaceful dissent must remain an essential channel for expressing political disagreement. Equally, demonstrators are expected to follow lawful procedures. The larger question is whether administrative restrictions can ensure public order without unnecessarily narrowing the space for political dissent. The answer lies in transparent rules, proportionate enforcement and equal treatment of all political parties.

Arunachal's Pakke Kessang Becomes First District to Install Official Boundary Pillar Along Assam Border

Jan Jan Vichar
...✍Itanagar



In a significant development in the long-running effort to resolve boundary-related issues between Assam and Arunachal Pradesh, Pakke Kessang has become the first district in Arunachal Pradesh to erect an official boundary pillar along the inter-state border. The boundary pillar has been installed at Dikalmukh in Pakke Kessang district, formally marking a demarcated section of the Assam–Arunachal Pradesh boundary. Arunachal Pradesh Health and Family Welfare Minister and Seijosa MLA Biyuram Wahge was present at the site during the installation. The initiative represents an important administrative step towards clearly identifying the shared boundary and strengthening the process of demarcation at the district level. It also highlights the role of district administrations in translating broader inter-state boundary-resolution efforts into concrete action on the ground.

In recognition of its work on the boundary-demarcation initiative, the Pakke Kessang District Administration has been nominated for the Arunachal Pradesh Chief Minister's Award.

A Step Towards Lasting Boundary Clarity

The boundary between Assam and Arunachal Pradesh has remained a longstanding issue, involving areas where questions of territorial jurisdiction and local interests have required sustained engagement between the two states. In recent years, both governments have undertaken efforts to address these disputes and establish clearer boundaries through dialogue and administrative coordination. The installation of the pillar at Dikalmukh adds a visible marker to this process. However, the significance of the development will ultimately depend on continued cooperation between the two states, adherence to agreed demarcation arrangements and effective communication with communities living along the border.

For residents of border areas, clearly identified boundaries can help reduce uncertainty and support better coordination in administration and development activities. Pakke Kessang's initiative could also provide an administrative example for other districts along the inter-state boundary. While one boundary pillar cannot resolve every outstanding issue, it represents a tangible step towards greater clarity. The larger challenge now is to sustain the momentum through peaceful dialogue, transparent demarcation and cooperation between Assam and Arunachal Pradesh, ensuring that boundary management becomes a foundation for stability rather than a source of recurring tension.

Canada's Unity Debate Is Under the Spotlight

Jan Jan Vichar
...✍New Delhi

Canada is once again confronting an uncomfortable question about the limits of national unity. In October, two very different separatist narratives are drawing attention in the country at almost the same time. One is rooted in Alberta's long-running grievances against Ottawa and demands for greater provincial autonomy, with some activists advocating eventual independence. The other is the Khalistan separatist campaign, promoted by groups seeking the creation of a separate Sikh state in parts of India. The two movements have entirely different histories, political objectives and constitutional contexts. Yet their proximity in time has created an unusual political spectacle-and has brought Canada's broader debate over separatism back into focus.

Alberta: A vote about a future vote

Alberta's proposed October 19 referendum should not be misunderstood as a direct vote on whether the province will leave Canada. The question concerns whether the provincial government should begin the constitutional process necessary to hold a future binding referendum on Alberta's separation from Canada. That distinction is crucial. Even a favourable result would not automatically make Alberta independent. It would instead strengthen the political argument for taking the next constitutional steps. Alberta has long had a complicated relationship with Canada's federal government. Questions surrounding energy policy, federal taxation, resource development, climate policy and the distribution of political power have periodically fuelled western alienation. For supporters of Alberta independence, the argument is that the province contributes enormous economic resources to the federation while having insufficient influence over national decision-making. Opponents, however, argue that separation would carry enormous economic, legal and political risks and that Alberta's interests can be pursued more effectively within Canada.



The referendum campaign therefore represents more than a simple independence slogan. It reflects a deeper dispute over federalism, resources, regional identity and political power.

Then there is Khalistan

Almost simultaneously, an entirely different separatist campaign is expected to attract attention in Edmonton. The organisation Sikhs for Justice (SFJ), associated with India-designated terrorist Gurpatwant Singh Pannun, has announced a Khalistan-related event in the Canadian city on October 18. The campaign seeks support for the creation of a separate Khalistan state in India. It is important to understand that such an exercise is not an official referendum conducted by the Canadian government and does not have the constitutional authority to redraw India's borders. Nevertheless, the events have repeatedly generated controversy because India regards the Khalistan movement as a serious national-security threat, while Canada has faced criticism from New Delhi over the activities of some separatist elements operating from Canadian soil.

A coincidence that has political symbolism

The timing is what makes the situation particularly striking. One day before Alberta's scheduled vote, a Khalistan-related separatist event is planned in Edmonton. The two campaigns are not formally connected, and there is no basis to treat them as a single movement. Yet their simultaneous presence highlights an increasingly complicated reality for Canada: separatist politics can emerge from very different sources and grievances within the same political system. Alberta separatism is essentially a domestic constitutional dispute involving a Canadian province and the federal state. Khalistan separatism, by contrast, concerns the territorial integrity and sovereignty of another country—India. Conflating the two would therefore be misleading. But ignoring the broader political symbolism would also be difficult.

Canada's delicate balancing act

Canada has traditionally presented itself as a multicultural democracy in which freedom of expression, political association and peaceful protest are strongly protected. That creates a difficult balancing act when political expression involves separatist causes. A government may permit individuals to express support for a political idea while simultaneously refusing to recognise that idea as having legal or constitutional force. This distinction becomes particularly sensitive when a movement is accused of supporting violence or is associated with individuals designated as terrorists by another country. For India, the issue is not merely theoretical. New Delhi has repeatedly raised concerns over the presence and activities of Khalistan separatists in Canada. Ottawa, meanwhile, has had to balance its domestic legal framework with diplomatic relations and India's security concerns. The result has been a relationship marked by repeated friction.

Pannun's political calculation

For Gurpatwant Singh Pannun and organisations associated with him, high-profile events in Canada provide an international platform for the Khalistan campaign. The timing of the Edmonton programme, close to Alberta's own separatist debate, may offer an opportunity to attract media attention. But attention should not be confused with political legitimacy. A privately organised referendum or polling exercise cannot by itself create a new country, alter India's territorial boundaries or impose any obligation on either India or Canada. Its significance lies primarily in political messaging, mobilisation and publicity. That distinction is essential in an age when social-media campaigns can make symbolic events appear far more consequential than their actual legal or political status.

A warning against simplistic comparisons

It would be tempting to portray Canada as a country collapsing under the weight of multiple separatist movements. That would be an exaggeration. Canada remains a functioning constitutional federation, and Alberta's independence movement does not represent the position of the province as a whole. Likewise, the Khalistan campaign should not be equated with Canada's Sikh population or with Canadian Sikhs generally. Millions of Sikhs around the world have no association with separatist politics.

The real story is therefore more nuanced. It is about how democratic freedoms, regional grievances, diaspora politics and international disputes can intersect within one political space.

The bigger question for India

For India, developments in Canada will be watched closely. The Khalistan issue has become one of the most contentious subjects in India-Canada relations. New Delhi wants Canada to prevent its territory from being used for activities it considers threatening to India's sovereignty and security. Ottawa, for its part, must navigate freedom-of-expression protections while addressing legitimate security concerns. The challenge is to distinguish between lawful political expression and activities that cross the line into intimidation, incitement or support for violence. That distinction will matter increasingly as diaspora politics becomes more influential in international affairs.

EDITORIAL

Harmanpreet : A Captaincy That Changed the Game

Every great sporting journey is measured not merely by trophies, but by the barriers it breaks and the confidence it inspires. Harmanpreet Kaur's decision to step down as India's captain across all three formats marks the end of a defining chapter in women's cricket. Her legacy, however, extends far beyond the boundaries of the cricket field.""Harmanpreet helped transform Indian women's cricket from a sport struggling for recognition into a source of national pride. Her aggressive batting, fearless approach and determination to challenge the strongest opponents changed perceptions about what Indian women could achieve. Her unforgettable 171 not out against Australia in the 2017 World Cup remains a landmark performance, symbolising courage under pressure and the arrival of a new sporting mindset. Her journey was not without disappointments. World Cup heartbreaks, criticism of her leadership and questions about succession tested her resolve. Yet, she continued to shoulder responsibility and compete at the highest level. Such resilience is an essential part of leadership, even when victories do not always follow. Her reported decision to relinquish captaincy after a series of major achievements offers an opportunity for Indian cricket to embrace renewal without abandoning experience. Smriti Mandhana and the emerging generation must now build on the foundation laid by their predecessors. The transition must be guided by merit, preparation and institutional support rather than the burden of expectations alone.""The larger lesson is clear: women's cricket needs sustained investment, stronger domestic structures, equal professional opportunities and public recognition beyond occasional triumphs. Harmanpreet may be handing over the captain's armband, but leadership is not confined to a designation.

India Is Both Overmedicated and Massively Undertreated

Jan Jan Vichar
...✍Chandrakant Lahariya

The country needs stronger primary care and more proportionate, patient-centred treatment The right medicine, for the right person, at the right time must be the goal. (Representative image) India has a peculiar healthcare problem. Some people are getting too much medicine, while others are not getting enough. In one part of the country, patients are being over-tested, over-scanned, over-supplemented and over-prescribed. In another, millions still struggle to obtain a basic consultation, a blood pressure check, a timely diagnosis or an essential medicine. One India is drowning in medical intervention. The other is waiting for it.

Consider two patients. The first lives in a large city and visits a private hospital because he feels tired. A battery of tests is ordered. Vitamin D is low, uric acid is slightly high, cholesterol is borderline, and several numbers are highlighted in red. Within days, he has acquired new diagnoses, new tablets, supplements and advice to repeat the tests in a few months. The second patient lives in a small town or village. His blood pressure has been high for years, but nobody has monitored it regularly. Diabetes is diagnosed late. Medicines are taken intermittently because they are not always available or follow-up is difficult. He reaches a hospital only when a stroke, kidney problem or another serious complication occurs. Both patients are victims of the same health system. One receives more medicine than he may need. The other receives less than he certainly needs.

This is one of the central paradoxes of Indian healthcare today. Half the problem is overtreatment and the other half is undertreatment. In urban India, healthcare is increasingly driven by the assumption that more must be better. More tests appear to mean greater thoroughness. More scans suggest greater caution. More medicines create the impression of more active treatment. But good medicine has never been about doing the maximum. It is about doing what is necessary.

Not every abnormal number is a disease. Not every disease requires an immediate drug. And not every prescription makes a person healthier. A raised uric acid level is not the same as gout. A low vitamin D result does not automatically make someone ill. A single cholesterol value cannot define cardiovascular risk. Age, blood pressure, diabetes, smoking, family history, body weight and physical activity all matter. Clinical decisions must be made by looking at the whole person, not one number printed in bold on a report.

Yet medicine is becoming increasingly report-centred rather than patient-centred. The patient may say, "I feel perfectly well", while the laboratory report says that one value is outside the normal range. Too often, the number wins. That is how overdiagnosis begins. One test leads to another. A minor abnormality gets a medical label. The label generates a prescription. The prescription then continues for months or years, sometimes without anyone asking whether it was necessary in the first place. This is not harmless. Unnecessary medicines can cause side-effects. Excessive testing can generate false-positive results and incidental findings. Scans may detect abnormalities that would never have caused disease but now trigger anxiety, repeated investigations and even procedures. Costs rise, worry increases and a healthy person starts living like a patient. More healthcare is not always better healthcare. But move away from the better-served pockets of the country and the picture changes dramatically. Primary care remains uneven. Hypertension often goes undetected or poorly controlled. Diabetes is diagnosed late. Pregnant women, older people and those living with chronic illnesses may not get regular follow-up. Mental health services remain thin. In many areas, even uninterrupted access to essential medicines cannot be taken for granted. The contradiction is extraordinary. In one city, a person may be undergoing a third MRI for a minor complaint, while somewhere else another person has never had his blood pressure measured properly. One family spends thousands of rupees every month on vitamins, protein powders and supplements of questionable value. Another struggles to obtain one inexpensive medicine that could prevent a stroke. These are not two separate health problems. They arise from the same failure to ask a simple question: Who needs what? The solution is not merely more hospitals, more machines and more specialists. India needs stronger primary healthcare and greater emphasis on clinical judgement. We need doctors who see people rather than laboratory panels; clinicians who know when to investigate, when to wait, when to advise lifestyle change and when specialist intervention is genuinely necessary. We also need to restore the distinction between fast medicine and slow medicine. Fast medicine saves lives. A heart attack, stroke, severe infection, major trauma or another emergency demands quick decisions and aggressive treatment. But every medical problem is not an emergency. Borderline cholesterol, mildly raised uric acid, age-related changes and minor abnormalities without symptoms often allow time. Diet can be improved. Weight can be reduced. Physical activity can increase. Sleep, smoking, alcohol use and stress can be addressed. The patient can be observed before another pill is added. Good medicine does not always mean doing something. Sometimes it means deliberately not doing something unnecessary. Not prescribing an antibiotic for a viral infection is good medicine. Not ordering an MRI for uncomplicated back pain can be good medicine. Not recommending a supplement simply because a laboratory value is outside a reference range can also be good medicine. But restraint should never become neglect. If a person genuinely needs antihypertensive treatment, it should not be delayed. Diabetes should be diagnosed and treated properly. Vaccines should reach those who need them. Serious symptoms should be investigated promptly. India, therefore, has to fight two battles at once: unnecessary medicine for some and inadequate medicine for others. Citizens need to understand that every test is not useful, every supplement is not beneficial and every abnormal report does not demand a tablet. At the same time, the health system must ensure that people who genuinely need care receive timely diagnosis, affordable treatment and essential medicines. The problem is not medicine. The problem is medicine without proportion.

Foreign Visitors Are Coming to Gaya to Honour Their Ancestors

Jan Jan Vichar
...✍Feature Desk



In the crowded lanes of Gaya during Pitru Paksha, where thousands of pilgrims gather every year to remember their ancestors, an unusual group of visitors quietly drew attention this year. They had travelled from Russia. They were not tourists merely looking for another cultural experience. They had come to perform pind daan and tarpan for their departed ancestors-a ritual rooted deeply in Hindu tradition and traditionally performed for the peace and liberation of departed souls.

Five Russian women-Nina Hara, Anastasia Ismagilova, Yulia Lavrentieva, Ksenia Abramova and Lyudmila Shalamova-performed the rituals at Devghat near the Vishnupad area. They also offered tarpan on the banks of the Falgu River and prayed for the peace of their departed family members.

For them, however, the experience was more than a religious ceremony. It was an emotional journey into the idea of remembering one's ancestors. One of the visitors, Alice, who came from Russia, described the experience as her first such visit to Gaya. She expressed the hope that her father and grandparents would find peace through her prayers and rituals. I hope my father, grandmother and grandfather find peace through this effort," she said, describing Gaya as a deeply sacred place.

An ancient tradition, a modern global interest

The sight of foreign visitors participating in Pitru Paksha rituals raises a larger question: Why are people from outside India becoming increasingly interested in ancient Indian spiritual and cultural traditions? For centuries, Gaya has been regarded as one of the most important places for performing rituals for ancestors. In Hindu belief, pind daan and tarpan are acts of remembrance, gratitude and spiritual responsibility towards one's forefathers. The foreign visitors who came this year appeared particularly moved by this aspect of the tradition. One of them said that Gaya gave her an opportunity to witness how people continue to respect their ancient customs and traditions. She also spoke of the hospitality and sense of security she experienced during her visit. For her, this was not her first encounter with the tradition. She had visited Gaya three years earlier and had already participated in the rituals.

What struck her was that interest in Hindu traditions appeared to be growing. People are beginning to take an interest in Hindu traditions"The visitors said they were drawn to the idea of respecting one's ancestors and understanding the spiritual meaning attached to that relationship. Their words were striking because they reflected something universal: the desire to remember parents, grandparents and generations that came before us. Regardless of nationality, culture or language, grief and gratitude towards one's ancestors are deeply human emotions. The rituals at Gaya gave these visitors a cultural framework through which they could express those emotions. Their participation also illustrates how traditions that originated thousands of years ago can continue to find meaning among people living far beyond India.

Gaya: Where memory becomes ritual

For Indians, particularly Hindus, Pitru Paksha is traditionally a period of remembrance. Families perform rituals for deceased parents, grandparents and other ancestors, believing that such acts express filial duty and help bring peace to departed souls. Gaya occupies a special position in this tradition. The city is associated with the Vishnupad Temple, the Falgu River and centuries-old practices surrounding ancestral rites. During Pitru Paksha, the city becomes a meeting point for faith, memory and family traditions. But the presence of foreign visitors adds another dimension to the annual gathering. They are approaching the tradition from outside the cultural environment in which it evolved. Yet, once they participate, their experience becomes intensely personal.

Beyond religion: A search for connection

The story of these Russian women is also a reminder that spirituality is not always about conversion or religious identity. Sometimes, it is about searching for meaning. In an increasingly fast-moving world, where families are scattered across countries and generations often live far apart, traditions that connect people with their ancestors can acquire a new significance. The foreign visitors appeared to be responding to precisely this emotional dimension. Their journey to Gaya was ultimately about people they had lost but had not forgotten. They came to perform rituals that were unfamiliar to their own cultural background, yet the emotions behind those rituals-love, gratitude, remembrance and the desire for peace-were universal.

A cultural bridge between India and the world

According to Jagdish Shyam Das, president of ISKCON in Patna, the five Russian women performed tarpan and pind daan on the banks of the Falgu River as an expression of love, gratitude and reverence towards their ancestors. They were reportedly encouraged to visit Gaya by Yulia Kushka, a foreign visitor who had herself previously participated in the rituals. That detail is significant. Cultural traditions often travel not through institutions but through personal experiences. One visitor tells another. One experience inspires another journey. And slowly, a local tradition becomes part of a wider global conversation.

What Gaya offered them

The foreign visitors did not come to Gaya merely to observe an ancient ritual from a distance. They participated in it. They stood beside the Falgu River, remembered their departed family members and performed ceremonies that have been part of Gaya's cultural landscape for generations. Their presence offered an unexpected image of India: not simply a country of monuments, festivals and tourism, but a civilisation where memory itself can become a ritual. For the people of Gaya, the arrival of foreign pilgrims may have been unusual. For the visitors, it appears to have been deeply personal. And perhaps that is the most powerful message emerging from this year's Pitru Paksha Mela. Traditions may belong to particular cultures, but remembrance belongs to all of humanity. In Gaya, five women from Russia came looking for a way to honour those they had lost.""They found a ritual. They also found a connection-between the living and the departed, between an ancient Indian tradition and a modern global audience, and perhaps most importantly, between their own memories and a culture thousands of kilometres away.

NANA PATEKAR: THE ACTOR WHO NEVER NEEDED TO SHOUT TO BE HEARD

Indian cinema has produced countless stars, but only a handful of actors have possessed the ability to make audiences uncomfortable, thoughtful and deeply emotional through a single expression. Nana Patekar belongs to that rare category. An actor of extraordinary intensity, he built a career not on conventional glamour but on authenticity, emotional complexity and an uncompromising commitment to his craft. With his sharp gaze, unmistakable voice and unpredictable screen presence, Patekar created a cinematic identity that was entirely his own. He could be menacing without becoming a caricature, vulnerable without appearing weak, and humorous without losing his natural edge. His performances repeatedly demonstrated that acting is not merely about delivering dialogue; it is about making every word, silence and gesture meaningful.



The making of an unconventional star

Born Vishwanath Patekar on January 1, 1951, in Murud-Janjira, Maharashtra, Nana Patekar did not follow the conventional path to stardom. His early association with theatre helped develop the discipline, precision and emotional depth that would later define his film career. He entered the film industry at a time when mainstream Hindi cinema often celebrated larger-than-life heroes. Patekar offered something different. His characters frequently carried the imperfections, anger, contradictions and anxieties of ordinary human beings. He did not always seek to make his characters likeable; instead, he made them believable. His performances in films such as Parinda, Prahaar, Angaar, Krantiveer and Ab Tak Chhappan established his reputation as an actor capable of portraying both explosive authority and deeply troubled humanity. In Parinda, his portrayal of a violent underworld figure demonstrated how menace could emerge from psychological complexity rather than theatrical exaggeration. In Prahaar, he brought the discipline and emotional burdens of a soldier to the screen. And in Krantiveer, his forceful performance transformed anger against injustice into one of the film's defining dramatic elements. These were not simply memorable roles. They reflected an actor who was willing to explore uncomfortable corners of human nature.

Beyond the image of the angry man

Patekar's screen persona is often associated with intensity, confrontation and powerful dialogue. Yet his contribution to Indian cinema cannot be reduced to the image of an angry man. He demonstrated remarkable versatility in films such as Welcome, where his portrayal of Uday Shetty revealed a flair for comedy and impeccable timing. The character's exaggerated seriousness, unexpected vulnerability and comic reactions introduced his talent to audiences who may previously have associated him primarily with intense dramatic roles. In Natsamrat, his performance as an ageing theatre actor confronting loneliness, family conflict and the fading relevance of his own greatness brought another dimension to his artistry. The film drew on the emotional traditions of Marathi theatre and explored the painful distance between public admiration and private suffering. His work in Apaharan and other dramatic films further reinforced his ability to inhabit morally complicated characters without offering easy answers.

Patekar's strength lay in his refusal to become predictable. Even when playing powerful or intimidating figures, he often allowed flashes of insecurity, tenderness or absurdity to emerge. These contradictions gave his characters an enduring human quality.

Awards, recognition and artistic credibility

Over the years, Patekar earned major recognition for his contribution to Indian cinema, including National Film Awards and Filmfare honours. His performance in Parinda earned him the National Film Award for Best Supporting Actor, while his work in Krantiveer received widespread acclaim. In 2013, he received the Padma Shri, one of India's highest civilian honours, in recognition of his contribution to the arts. Yet awards alone cannot explain his significance. His larger achievement was to establish a place for an actor whose appeal did not depend on conventional leading-man attributes. He proved that a performer could command the screen through character, conviction and craft. He also remained associated with Marathi cinema and theatre, maintaining a connection with the regional artistic traditions that helped shape his sensibilities.

The artist and the questions beyond cinema Like several public figures, Patekar's life beyond the screen has also attracted public scrutiny and debate. Allegations, denials and legal developments involving public personalities must be assessed carefully, on the basis of verified reporting and established facts rather than rumour or social-media speculation. An honest account of an artist should neither erase legitimate questions nor allow controversy to replace an examination of the work. The distinction between a person's public conduct and artistic achievement is often complicated, but responsible journalism must preserve that distinction while acknowledging matters of genuine public interest. Patekar's career therefore invites a broader discussion about celebrity, accountability and the tendency to treat public figures as either flawless icons or irredeemable personalities.



Printed & Published by Purvanchal Prints, GMCH Road, Harbala Market, Bhangagarh, Guwahati-781005 Contact: 69001 26012
Email : Official.janjanvichar@gmail.com,Website : www.janjanvichar.in ● Executive Editor : Subhash Kumar Choudhary ● Editor : Dhaneshwar Choudhary